A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 11 जुलाई, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 309, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

पीएम मोदी ने इंडो पेसिफिक के सारे समीकरण बदल दिए

नीरज कुमार दुबे

भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बदलती वैश्विक राजनीति में दोनों देश केवल पुराने मित्र नहीं, बल्कि भविष्य के रणनीतिक साझेदार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को नई मजबूती दी है। जकार्ता में जिस गर्मजोशी और सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, उसने साफ संकेत दिया कि भारत अब एशिया की राजनीति, सुरक्षा और विकास की दिशा तय करने वाली प्रमुख शक्ति बन चुका है। देखा जाये तो प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा लोकतंत्र, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की मजबूत नींव भी साबित हुई।

इंडोनेशिया की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण रहा। उन्होंने भारत और इंडोनेशिया को केवल दो देश नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जुड़े सभ्यतागत साझेदार बताया। रामायण, महाभारत, नालंदा और प्रम्बानन मंदिर का उल्लेख करते हुए मोदी ने साफ कहा कि समुद्र ने दोनों देशों को कभी अलग नहीं किया, बल्कि यही समुद्र दोनों को जोड़ने वाला पुल बना। उनका यह संदेश केवल सांस्कृतिक संदेश नहीं था, बल्कि इंडो पैसिफिक की नई भू-रणनीतिक सोच का संकेत भी था।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिस दृढ़ता से कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद के मार्ग पर चलता है, वह सीधे तौर पर उस वैश्विक शक्ति संतुलन की ओर इशारा था जहां कई ताकतें समुद्री इलाकों पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रही हैं। मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और इंडोनेशिया यदि साथ खड़े होते हैं तो लोकतंत्र पर दुनिया का भरोसा और मजबूत होगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक राजनीति का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है।

इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि दोनों देशों के बीच हुए 20 ऐतिहासिक समझौते रहे। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, दुर्लभ खनिज, दूरसंचार, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल ढांचा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हुए ये समझौते आने वाले वर्षों में भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाले हैं। सबसे अधिक चर्चा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर हुए समझौतों की रही। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक संतुलन को मजबूत करने वाला कदम है।

देखा जाये तो भारत द्वारा इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित इंडोनेशिया वैश्विक समुद्री व्यापार का अहम केंद्र है। दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया के तटरक्षक बलों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ना सीधे तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह साझेदारी समुद्री डकैती, अवैध गतिविधियों और किसी भी प्रकार की आक्रामक विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में महा सागर दृष्टि का उल्लेख करते हुए साफ कहा कि भारत मुक्त, खुला और नियम आधारित इंडो पैसिफिक चाहता है। यह संदेश पूरी दुनिया और खासतौर पर चीन के लिए था कि भारत किसी गुट की राजनीति नहीं बल्कि संतुलित और स्थिर वैश्विक व्यवस्था का समर्थक है। आसियान की केंद्रीय भूमिका पर भारत का जोर यह भी दिखाता है कि नई दिल्ली दक्षिण पूर्व एशिया को केवल व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी मानती है।

हम आपको बता दें कि मोदी की इस यात्रा में तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में हुए समझौते भी बेहद महत्वपूर्ण रहे। भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के आधार पर इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क की शुरुआत, भुगतान प्रणाली को जोड़ने की तैयारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा स्टार्टअप सहयोग पर सहमति इस बात का संकेत है कि भारत अब तकनीकी नेतृत्व की दिशा में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु का परिसर इंडोनेशिया में खोलने का फैसला शिक्षा और ज्ञान कूटनीति के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं को अपनाया है। उन्होंने हंसी मजाक में कहा कि उन्हें खुशी है कि इन योजनाओं पर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन इस हल्के फुल्के बयान के भीतर भारत के विकास मॉडल की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता का बड़ा संदेश छिपा था। इंडोनेशिया द्वारा भारत की कृषि तकनीक, सूखी जमीन को उपजाऊ बनाने के प्रयोग और जनकल्याण योजनाओं का अध्ययन यह दिखाता है कि दुनिया अब भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि समाधान देने वाले राष्ट्र के रूप में देख रही है।

प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण दिया जाना भी इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि रहा। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मोदी ने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा लोकतांत्रिक परंपराओं तथा सभ्यतागत रिश्तों को समर्पित किया। यह सम्मान बताता है कि दुनिया में भारत की साख पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है।

साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच दुर्लभ खनिज, इस्पात आपूर्ति श्रृंखला और दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों पर हुए समझौते भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बेहद अहम हैं। आने वाले समय में प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन के लिए दुर्लभ खनिजों की भूमिका निर्णायक होगी। ऐसे में भारत का इंडोनेशिया के साथ इस क्षेत्र में साझेदारी करना दूरगामी रणनीतिक सोच का परिचायक है। देखा जाये तो भारत अब दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह विकास, लोकतंत्र, सुरक्षा और सांस्कृतिक शक्ति का ऐसा संगम है जो वैश्विक व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।

बहरहाल, मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने भारत को रक्षात्मक सोच से निकालकर निर्णायक वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में पहुंचा दिया है। कभी केवल दक्षिण एशिया तक सीमित माना जाने वाला भारत आज इंडो पैसिफिक की धुरी बन चुका है। दुनिया के बड़े राष्ट्र भारत के साथ साझेदारी को अपनी रणनीतिक आवश्यकता मान रहे हैं। इंडोनेशिया यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव, सामरिक दूरदृष्टि और वैश्विक प्रभाव का नया अध्याय लिख रही है।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मालदा में बांग्लादेश बॉर्डर पर

फटक नहीं पाएंगे घुसपैठिए

● मेगा प्लान तैयार, बीएसएफ की मदद के लिए खुलेंगे नए थाने

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से लगने वाले बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए नए सिरे से फुलप्रूफ प्लानिंग की गई है। नई प्लानिंग में खुले इलाकों की बाड़बंदी, बीएसएफ की चौकसी के साथ लोकल पुलिस की तादाद बढ़ाने की तैयारी है। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने और इन इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तीन नए पुलिस स्टेशन और दो नई पुलिस चौकी बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकी बनते ही इलाके में 75 नए अफसर और 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हो जाएंगे।

पिछले दिनों बांग्लादेशी गार्डों से हुआ था तनाव

पश्चिम बंगाल के मालदा से जुड़े बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसपैठ करते रहे हैं। गोवंश और ड्रग्स की तस्करी के नजरिये से भी यह बॉर्डर सेंसेटिव रहा है। इन इलाकों में बांग्लादेशी आए दिन उपद्रव भी करते हैं। इंटेलीजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, मालदा में क्राइम के पीछे भी बांग्लादेशी दलालों का बड़ा रोल होता है। 2023 में बीएसएफ ने साउथ बंगाल बॉर्डर से घुसपैठ कराने वाले 53 दलालों को पकड़ा था।

बॉर्डर किनारे बसे गांवों को भी मिल जाएगी राहत

हबीबपुर के बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री जोएल मुर्मू ने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटे मालदा के हबीबपुर, वैष्णवनगर और कालियाचक के बड़े हिस्से में अभी बाड़बंदी नहीं हुई है। खुले बॉर्डर के कारण निगरानी करना काफी मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश से घुसपैठ और उपद्रव की सूचना या शिकायत देने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पुलिस को भी वहां पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। इस हालात से निपटने के लिए वैष्णवनगर के कुंभीरा, गोलापगंज और बुलबुलचंडी पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया गया है। मालदा के एसपी अनुपम सिंह के मुताबिक हबीबपुर के जजैल और बामनगोला के जगदला में भी दो नए पुलिस आउटपोस्ट बनाए जाएंगे। इस अपग्रेडेशन के बाद हर नए पुलिस स्टेशन में करीब 20 अधिकारी और 50 पुलिसकर्मी हो जाएंगे। बीएसएफ से बंगाल पुलिस का कोर्डिनेशन भी सुधर जाएगा।

अतिथि विद्वानों के मुद्दों पर बनेगी कमेटी

सीएम बोले- फिक्स सैलरी, नियमितीकरण समेत मांगों पर होगा विचार, अटकाने-लटकाने का समय गया

भोपाल (नप्र)। भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वानों की फिक्स सैलरी, नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों पर विचार के लिए कमेटी बनाई जाएगी। देश के जिस भी राज्य का बेहतर मॉडल होगा, उसका अध्ययन कर मध्यप्रदेश में लागू करने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटकाने-लटकाने का समय गया, अब सरकार सकारात्मक सोच के साथ फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री ने रवींद्र भवन में आयोजित प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से कहा कि वे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समिति बनाकर अतिथि विद्वानों की मांगों पर काम करें। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव सहयोग करेगी।

फिक्स सैलरी और नियमितीकरण पर होगा मंथन- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले भी अतिथि विद्वानों के लिए कई फैसले ले चुकी है। अब उनकी बाकी समस्याओं के समाधान की दिशा में भी काम होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा समेत जिस राज्य में बेहतर व्यवस्था है, उसका अध्ययन कर मध्यप्रदेश में लागू करने पर विचार किया जाएगा।

शिक्षा से ही बनेगा मजबूत समाज

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय शिक्षा परंपरा का उल्लेख करते हुए भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रसंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था हमेशा दुनिया के लिए प्रेरणा रही है और नई शिक्षा नीति के जरिए मध्यप्रदेश देश में मिसाल बना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर है और अब किताबी ज्ञान के साथ नवाचार पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार पहले ही दे चुकी कई सुविधाएं- उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार ने अतिथि विद्वानों को 13 आकस्मिक अवकाश, तीन ऐच्छिक अवकाश, महिला अतिथि विद्वानों को प्रसूति अवकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण और साल में एक बार स्थानांतरण की सुविधा दी है। उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग में वेतन 12 महीने के बजाय 11 महीने मिलने की समस्या को भी दूर किया जाएगा, ताकि दोनों विभागों के अतिथि विद्वानों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके।

मजदूर संघ ने उठाए सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे

भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने कहा कि अतिथि विद्वानों की सामाजिक सुरक्षा और अन्य लंबित मांगों का जल्द समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास से मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

सुप्रभात

ये दिन
प्रकाश के नहीं
घोर अंधेरे के हैं

ये दिन
जीवन के नहीं
मृत्यु के हैं

ये दिन
शांति के नहीं
हाहाकार के हैं

ये दिन
सुधारसपान के नहीं
गरलपान के हैं

ये दिन
दूब के नहीं
गाजरघास के हैं

ये दिन
हमारे नहीं
तुम्हारे नहीं
तानाशाह के हैं।

-दुर्गाप्रसाद झाला

बीजेपी ने दतिया से आशुतोष तिवारी को बनाया उम्मीदवार

भोपाल (नप्र)। दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। माना जा रहा था कि यहां से बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को टिकट देगी। नरोत्तम मिश्रा 2023 में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेन्द्र भारती से अपना चुनाव हार गए थे।

राजेंद्र भारती को हाईकोर्ट से राहत नहीं, सजा बरकरार, उपचुनाव पर कानूनी अनिश्चितताएं खत्म

नई दिल्ली/दतिया। दतिया के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त किए जाने का फैसला बरकरार रहने का रास्ता साफ हो गया है और दतिया विधानसभा उपचुनाव पर लगी कानूनी अनिश्चितता भी खत्म हो गई है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2026 को दिल्ली की विशेष अदालत ने वर्ष 1998 के दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक एफडी धोखाधड़ी मामले में राजेंद्र भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) तथा जालसाजी से संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया था। इसके बाद 2 अप्रैल 2026 को अदालत ने उन्हें तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मामला दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक की एक एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) में कथित हेराफेरी से जुड़ा था। आरोप था कि बैंक रिकॉर्ड में फेरबदल कर एफडी की अवधि बढ़ाई गई और उस आधार पर ब्याज राशि प्राप्त की गई।

वायनाड का पहाड़ कभी भी गिर सकता है...

टनल हादसे से पहले इंजीनियरों ने दी थी चेतावनी

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरलम के वायनाड में मंगलवार को मेप्पाडी-कल्लाडी टनल रोड प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में अब तक सात लोगों की मौत हो गई है। यह कोई अचानक आई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक ऐसा हादसा था जिसकी भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। वायनाड सुरंग निर्माण कार्य के उप-ठेकेदार दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (डीबीएल) द्वारा तैयार की गई एक आंतरिक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि हादसे से पहले ही सुरंग के उत्तरी प्रवेश द्वार के ऊपर की पहाड़ी तेजी से टूट रही थी। इसमें साफ चेतावनी दी गई थी कि भारी बारिश और आंतरिक जल भराव के कारण यह ढलान (पहाड़) किसी भी समय अचानक ढह सकता है। चेतवानी के बावदूद सुरक्षा मानकों में लापरवाही हुई, जिसके कारण बारिश होते ही लैंडस्लाइड हुआ और सात मजदूरों की जान चली गई। यह आंतिरक रिपोर्ट डीबीएल के वरिष्ठ भूविज्ञानी राजू सागर, जीएसआई के ए रमेश कुमार और टर्किश इंजीनियरिंग कंसल्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग के प्राधिकरण अभियंता डॉ. एच.के. सिंह द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। दरअसल, इस निर्माणाधीन टनल की साइट का निरीक्षण करने वाले इंजीनियरों ने देखा कि टनल के मुहाने के ऊपर की पहाड़ी पर लगभग 35 मीटर मोटी, ढीली, गाद वाली मिट्टी की एक मोटी परत थी, यह मिट्टी कठोर चट्टान के ऊपर स्थित थी। ऐसे में मिट्टी का निकास ठीक से नहीं हो सकता। भारी बारिश के चलते पानी मिट्टी के अंदर ही भर जाता है, जिसके कारण मिट्टी भारी हो जाती है और खिसकने के चांस बढ़ जाते हैं। इस मिट्टी को स्थिर रखने के लिए कंपनी ने ढलान को सीढ़ियों के रूप में काटा था, उस पर शॉटक्रेट नामक कंक्रीट की एक पतली परत का छिड़काव किया था, और सॉइल नेल्स नामक धातु की छड़ें गाड़ दी थीं।

लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि निरीक्षण के वक्त ही ढलान ढहने लगी थी। इंजीनियरों ने निरीक्षण के दौरान कटी हुई सतह पर कई स्तरों पर दरारें चौड़ी होती देखीं, किनारों से मिट्टी खिसकती देखी, कीचड़ वाला पानी रिसता देखा और मिट्टी के अंदर ही गुहाएं बनती देखीं।

मिट्टी के भीतर भर रहा था पानी

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इंजीनियरों को ढलान के दो आधार स्तरों के बीच की खाई में भूमिगत जल प्रवाह की आवाज सुनाई दी। यानी इसका साफ मतलब था कि पानी ने ढीली मिट्टी में एक गुप्त रास्ता बना लिया था और यह पानी उसके भीतर भर रहा था। ऊपर से भले ही ठोस दिख रहा था, लेकिन वह धीरे-धीरे पहाड़ी को अंदर से बहा रहा था। इसको लेकर इंजीनियरों ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि इस तरह का आंतरिक कटाव ढलान को तेजी से कमजोर कर सकता है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 11 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

श्रीति - संदीप राशिनकर पुणे में सम्मानित

इंदौर। शहर के चित्रकार, लेखक संदीप और श्रीति राशिनकर को उनकी दीर्घ साहित्य - कला साधना के अवदान के लिए सम्मानित किया गया। पिंपरी चिंचवड़ विधान सभा क्षेत्र में कला के माध्यम से समाज में रचनात्मकता के संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे समर्पित प्रयासों के लिए यह सम्मान उन्हें क्षेत्र के कर्मठ नेता रामभाऊ वाकड़कर द्वारा प्रदान किया गया।

12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने 12 फीसदी से ज्यादा अल्कोहल मिक्स दवाओं की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। अब ये दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकेंगी। दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में यह बदलाव किया है। नए नियम के तहत उन सभी पीने वाली दवाओं को 'शेड्यूल ॥1' कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इनमें एथिल अल्कोहल की मात्रा 12 फीसदी से ज्यादा होती है और जो 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतल में बेची जाती हैं।

मेडिकल स्टोर्स को 3 साल का रिकॉर्ड रखना होगा- मेडिकल स्टोर्स के लिए भी खास निर्देश हैं। अब मेडिकल स्टोर्स को इन दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में रखना होगा। मार्केट में मिलने वाले कई कफ सिरप और टॉनिक में अल्कोहल की मात्रा काफी

कफ सिरप और टॉनिक पर असर,ड्रग रूल्स 1945 में किया बड़ा बदलाव

ज्यादा होती है। बिना रोक-टोक या डॉक्टर की पर्ची के मिलने से कई लोग इनका इस्तेमाल नशे के लिए करने लगे थे। इसी दुरुपयोग को रोकने और दवाओं की बिक्री की सख्ती से निगरानी के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। दवाओं के गलत इस्तेमाल की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए सरकार की रेगुलेटरी कमेटियों- ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इस पर समीक्षा की थी। इन कमेटियों की सिफारिशों के बाद ही सरकार ने कानून में यह संशोधन लागू किया है। दवाओं में सीमित मात्रा में एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल एक सॉल्वेंट या प्रिजर्वेटिव (दवा को सुरक्षित रखने और घोलने) के रूप में किया जाता है, जो क्लीनिकल तौर पर जरूरी है। यह आमतौर पर हानिकारक नहीं होता।

लिवर के मरीजों के लिए गंभीर साइड इफेक्ट्स

हालांकि, जर्नल ऑफ मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसी दवाओं का बिना डॉक्टरी सलाह के या जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाए, तो यह बच्चों, बुजुर्गों और लिवर के मरीजों के लिए गंभीर साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। इस कदम से भारत में ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम और मजबूत होगा। दवाओं की ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी यानी यह पता लगाना आसान होगा कि क्या गलत है।

संक्षिप्त समाचार

करूर भगदड़

मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी दे सकेगी सरकार

चेन्नई (एजेंसी)। सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम(टीवीके) सरकार को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने शुक्रवार को करूर रैली में मची भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां पूरी तरह से अस्थायी होंगी और मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगी। जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस आर. शक्तिवेल की बेंच ने कहा कि वे इस स्तर पर सरकार के नीतिगत फैसले में दखल नहीं देना चाहते। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये नियुक्तियां याचिकाओं पर आने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होंगी। साथ ही यह भी तय किया कि लाभार्थियों को उनके पहले महीने का वेतन मिलने से पहले इस मामले की याचिकाओं पर सुनवाई की जाए।

टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल

पार्टी ने तीनों को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया

कोलकाता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने तीनों को बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद तीनों नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता और टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। तीनों ने ममता से नाराजगी जताई थी और कहा था कि पार्टी मनमाने ढंग से चल रही है। सुखेंदु ने 8 जून, सुष्मिता ने 10 जून और प्रकाश ने 11 जून को रिजाइन दिया था। बंगाल की इन तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 24 जुलाई को वोटिंग और काउंटिंग होगी। 14 जुलाई तक नामांकन और जांच 15 जुलाई को होगी।

दान गिनने वाले तेईस कर्मचारियों का इस्तीफा

- चढ़ावे में 10-20 रुपए के नोट बढ़े,500 के घटे

अयोध्या (एजेंसी)। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने और टीम के गठन के मांग की गई है। साथ ही, मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी मांग की गई है। इधर, मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने गुरुवार को एक साथ इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि चोरी की घटना के बाद 10-20 रुपए के नोट बढ़ गए हैं, जिससे गिनती में ज्यादा समय लग रहा है। पहले 500 रुपए के नोटों की 70-80 गड्डियां बन जाती थीं, अब बमुश्किल 15 गड्डियां बन रही हैं।

साहित्य संपादक निर्मोही जी का दुर्लभ साहित्य सप्रे संग्रहालय में

भोपाल। सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं हिन्दी की प्रतिष्ठित पत्रिका 'वीणा' के पूर्व संपादक कीर्तिशेष मोहनलाल उपाध्याय 'निर्मोही' की स्मृति में उनके परिवार ने भोपाल स्थित माधवराव सप्रे समाचारपत्र संग्रहालय को 700 दुर्लभ पुस्तकें भेंट की हैं।

10 जुलाई को निर्मोही परिवार के सुपुत्र सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. प्रकाश उपाध्याय एवं वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय ने सप्रे संग्रहालय के संस्थापक पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर को ये पुस्तकें भेंट कीं। ये पुस्तकें 90 वर्ष तक पुरानी हैं। इनमें से कई पुस्तकें दुर्लभ एवं अप्राप्य हैं। इनमें हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी व फ्रेंच भाषा के अलावा गुजराती व राजस्थानी भाषा की साहित्य, आलोचना, काव्य, गद्य, इतिहास, कोश, विषय की पुस्तकें शामिल हैं।

विजयदत्त श्रीधर ने उपाध्याय परिवार के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि निर्मोही संग्रहालय का यह बौद्धिक कोश, सप्रे संग्रहालय की संदर्भ-संपदा को और समृद्ध करेगा। देश-विदेश से यहाँ आकर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए विशिष्ट संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराएगा। डॉ. प्रकाश उपाध्याय ने आभार व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि निर्मोही परिवार की यह पूँजी अब सप्रे संग्रहालय में सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए संदर्भ का महत्वपूर्ण स्रोत बनेगी।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे और उनकी टीम को ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 अंतर्गत मध्यप्रदेश को राजत पदक मिलने पर बधाई दी।

प्रदेश में कोटे की 25 प्रतिशत बारिश पूरी

32 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी गिरा ; पन्ना, सतना में आज हेवी रेन का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में कोटे की 25 प्रतिशत यानी, 9.4 इंच बारिश हो गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 32 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी गिरा। मौसम केंद्र की मानें तो पूरे जुलाई पानी बरसेगा। इससे आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा।

मौसम विभाग ने 4 दिन तक प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हलकी बारिश का अनुमान जताया है। पन्ना और सतना जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। 24 घंटे के दौरान यहां 4 इंच या इससे ज्यादा पानी गिर सकता है।

इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, आलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम्, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी बारिश का अनुमान है।

मंडला में पौन इंच बारिश, ग्वालियर-जबलपुर समेत 11 जिलों में गिरा पानी- प्रदेश में गुरुवार को भी बारिश का दौर रहा। मंडला में पौन इंच पानी गिर गया। सिंगरौली में आधा इंच से अधिक और बालाघाट में आधा इंच बारिश हुई। बैतूल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, खजुराहो, सागर, सतना, सीधी में भी पानी गिरा।

चित्रकूट में उफान पर मां मंदाकिनी, रामघाट जलमग्न, श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील

लगातार हो रही बारिश का असर अब धर्मनगरी चित्रकूट में भी साफ दिखाई देने लगा है। आस्था की प्रतीक मां मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक करीब चार फीट बढ़ गया, जिससे प्रसिद्ध रामघाट की आठ सीढ़ियां पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। नदी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।जलस्तर में तेजी से हुई बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन रामघाट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी घाट पर तैनात हैं तथा श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को गहरे पानी के पास न जाने की लगातार समझाइश दी जा रही है। घाट पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

यूपी चुनाव के लिए बिहार से लाई जाएंगी 1300 ईवीएम

जीपीएस से लैस रहेंगे लाने वाले वाहन

ग्रेटर नोएडा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गौतमबुद्ध नगर में बिहार से 1300 ईवीएम मंगवाई जा रही हैं। साथ ही, प्रशासन मतदान केंद्रों के चयन में जुटा है और मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और मतदान केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। जिले में चुनावी मतदान व्यवस्था के लिए बिहार से ईवीएम मंगवाई जा रही हैं।

मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों के निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू- प्रशासन ने मतदान के लिए मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों के निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 749 मतदान केंद्र और 1922 मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं, जिस पर राजनीतिक दलों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। शहरी इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सोसायटियों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता विधानसभा चुनाव में हिस्सा लें।

सरकार ने भी माना

ई 20 पेट्रोल से माइलेज पर असर

- इथेनॉल विवाद के बीच आया नितिन गडकरी का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में ई20 फ्यूल, यानी पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने का मामला हर दिन नए मोड़ ले रहा है। देशभर की जनता माइलेज ड्रॉप होने और परफॉर्मेंस प्रभावित होने के साथ ही इंजन में कथित खराबी को लेकर अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं।

बिहार के पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप के दावों ने जैसे आग में घी का काम किया और जब विवाद ज्यादा गहरा गया तो

अब केंद्र की मोदी सरकार के एक अहम बाद स्वीकार की है। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना कि ई20 पेट्रोल से माइलेज पर हल्का असर होता है, लेकिन पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंजन में कोई खराबी नहीं आती।

- **माइलेज पर मामूली असर-** केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि इथेनॉल का कैलोरिफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होता है, जिसके कारण माइलेज में मामूली गिरावट आ सकती है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। सिटी ड्राइविंग कंडीशन (जैसे दिल्ली-मुंबई समेत अन्य महानगरों में ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाना) में माइलेज का अंतर ड्राइविंग स्टाइल पर ज्यादा निर्भर करता है, न कि केवल फ्यूल पर। ऐसे में जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि माइलेज घट गया है, यह भ्रामक है।

'इंजन में खराबी की खबरें भ्रामक'

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर इंजन खराब होने की जो खबरें चल रही हैं, इससे गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ई 20 को वाहन बनाने वाली कंपनियों द्वारा कड़े परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है। गड़करी ने चुनौती दी कि कोई एक भी कार दिखाएं, जो ई 20 ईंधन के कारण खराब हुई हो। गडकरी की मानें तो कुछ मामलों में जांच के बाद पता चला कि इंजन की खराबी का कारण मिलावटी ईंधन था, न कि ई 20 फ्यूल। आपको बता दें कि हाल ही में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने ई 20 फ्यूल से अपनी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस खराब होने का दावा किया और इसे लेकर नितिन गडकरी को जमकर कोसा, जिसके बाद ई20 फ्यूल को लेकर विवाद काफी ज्यादा फैल गया और सरकार को इस मामले में अब जवाब देना पड़ रहा है।

जगन्नाथ पुरी के राजा का राष्ट्रपति और पीएम को पत्र

कहा-इस्कान का अलग समय पर रथयात्रा निकालना गलत, इससे परंपरा खत्म हो जाएगी

भुवनेश्वर (एजेंसी)। पुरी के गजपति महाराज दिव्यसिंह देव ने इस्कान की तरफ से अलग तिथियों पर जगन्नाथ रथयात्रा और स्नान यात्रा निकालने पर आपत्ति जताई है। दिव्यसिंह देव ने 8 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है और हस्तक्षेप की मांग की है। दिव्यसिंह ने कहा कि इससे प्राचीन परंपरा खत्म हो जाएगी। गजपति महाराज दिव्यसिंह देब श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि इस्कान रथयात्रा का आयोजन ऐसी तारीखों पर कर रहा है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं हैं। इससे भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं।

- **इस्कान ने विदेशों में पहले मनाया उत्सव-** इस्कान ने 21 जून को लंदन, 14 जून को न्यूयॉर्क सिटी और 5 जुलाई को सिडनी में रथयात्रा निकाली थी। लेकिन इस साल, स्नान पूर्णिमा 29 जून को थी और पुरी में मुख्य रथयात्रा 16 जुलाई को होगी। इस्कान का कहना है कि भगवान जगन्नाथ पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के हैं। विदेशों में मौसम, स्थानीय परिस्थितियों और भक्तों की सुविधा को देखते हुए रथयात्रा की तारीखें अलग-अलग होती हैं ताकि ज्यादा लोग उत्सव में शामिल हों ।
- **मध्य प्रदेश में प्रस्तावित रथयात्राओं पर भी आपत्ति-** गजपति महाराज ने उज्जैन स्थित इस्कान मंदिर की ओर से 16 से 25 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश के 66 स्थानों पर रथयात्रा आयोजित करने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रथ यात्रा केवल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू होने वाला 9 दिवसीय उत्सव है। उन्होंने कहा कि महर्षि वेदव्यास रचित स्कंद पुराण में भी भगवान जगन्नाथ ने स्वयं स्नान यात्रा और रथयात्रा की निर्धारित तिथि बताई हैं। ऐसे में मनमानी तिथियों पर आयोजित करना गलत है।
- **महाराज देव के पूर्वजों ने किया था मंदिर का पुनर्निर्माण-** वर्तमान गजपति महाराज दिव्यसिंह देव भोई वंश से हैं। यह वंश भगवान जगन्नाथ की परंपरा के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि उन्होंने अफगान आक्रमणों के बाद पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा-परंपरा को फिर से व्यवस्थित किया था और मंदिर की धार्मिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। परंपरा के अनुसार, वे भगवान जगन्नाथ के प्रमुख सेवक माने जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान रथों पर सोने की झाड़ू से बुहारने की पवित्र सेवा होती है।

मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात

प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं की जनसमस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं को सुना। मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कार्यकर्ताओं द्वारा रखी गई जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं हो सका, उन्हें संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र निराकरण के लिए प्रेषित किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों के हित में बढ़ाया सामाजिक सुरक्षा का दायरा

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश ने संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण पहल करते हुए उनके और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है। अब पात्र संविदा कर्मचारियों तथा सेवा अवधि के दौरान निधन होने की स्थिति में उनके आश्रितों को उपादान (ग्रेच्युटी) राशि का लाभ दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों के परिजन को कठिन समय में आर्थिक संबल मिलेगा। इसी क्रम में 8 जुलाई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पहली बार एक दिवंगत संविदा कर्मचारी के आश्रित को मृत्यु उपरांत उपादान राशि का भुगतान किया गया। संविदा कर्मचारियों के कल्याण और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। अपर मिशन संचालक एनएचएम श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के पालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 26 अगस्त 2025 से उपादान भुगतान की प्रक्रिया लागू की गई है।

सांप ने पति-पत्नी, बेटी को डंसा, बेटी की मौत

रात ढाई बजे बिस्तर पर रेंगता दिखा करैत; दंपती की हालत गंभीर

अनूपपुर (नप्र)। अनूपपुर जिले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों को सांप ने काट लिया। अस्पताल ले जाते वक्त 6 साल की बेटी ने दम तोड़ दिया जबकि माता-पिता भर्ती हैं।घटना भेड़वाटोला गांव में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात की है। भानु प्रताप सिंह पत्नी रेखा सिंह और बेटी माधवी सिंह के साथ बिस्तर पर सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब ढाई बजे भानु प्रताप को अपने पैर की उंगलियों में किसी जीव के काटने का अहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उठकर देखा तो बिस्तर पर करैत सांप रेंग रहा था। भानु प्रताप ने तुरंत पत्नी और बच्चों को जगाया। परिवार के दूसरे लोगों को जानकारी दी। उनके भाइयों ने तुरंत गाड़ी की व्यवस्था की और पूरे परिवार को इलाज के लिए कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए लेकर रवाना हुए।

माता-पिता की हालत गंभीर, एंटी स्नेक वेनम लगाया

अस्पताल के रास्ते में करीब साढ़े 3 बजे माधवी को उल्टी हुई। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने भानु प्रताप और रेखा की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 5 बजे दंपती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें एंटी स्नेक वेनम लगाया है।

जांच के बाद चला कि पत्नी को भी सांप ने काटा है

माधवी के ताऊ अरुण सिंह ने कहा- हम केवल भानु प्रताप को ही सर्पदंश का शिकार समझ रहे थे। बच्ची को उल्टी होने और उसकी मौत के बाद अहसास हुआ कि सांप ने उसे भी काटा था। अस्पताल पहुंचकर भानु के साथ रेखा और बेटे का मेडिकल चेकअप कराया। इसमें रेखा को भी काटे जाने की पुष्टि हो गई। फिलहाल, पुलिस ने बच्ची के शव को मॉर्चुरी में रखवाया है क्योंकि परिवार के बाकी सदस्य अस्पताल में भर्ती पीड़ितों की देखरेख में जुटे हैं।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय से स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइड लाइन के संबंध में वीडियो कॉफ्रेंसिंग कर आवश्यक निर्देश दिये।

एक्सपो नए अवसरों, हुनर और निवेश का बड़ा मंच : राज्यमंत्री कृष्णा गौर

इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो-2026 का किया शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि इस तरह के इंडस्ट्रियल एक्सपो सिर्फ मशीनों को दिखाने तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये उद्योगों, नए विचारों, नवाचारों, स्किल डेवलपमेंट और निवेश के नए अवसर देने का एक बड़ा माध्यम बनते हैं। हमारे स्थानीय उद्योगों की तकनीकी तरक्की मध्यप्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार दे रही है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो-2026 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर आधुनिक मशीनों की कार्यप्रणाली को करीब से देखा। उन्होंने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में निर्मित मशीनों की गुणवत्ता, तकनीकी दक्षता और औद्योगिक क्षमता की सराहना करते हुए

कहा कि स्थानीय उद्योगों की तकनीकी प्रगति प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने का कार्य कर रही है। प्रदर्शनी में ऑटोमेशन, प्रिसिजन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल उपकरणों और अत्याधुनिक मशीनरी से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित उद्योगों ने अपनी तकनीकों का प्रदर्शन किया। एक्सपो का आयोजन फ्यूचर कम्युनिकेशन और गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में गोविंदपुरा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय गौड़ और फ्यूचर कम्युनिकेशन के श्री लक्ष्मण दुबे मौजूद रहे।

नशा, नाश की जड़ है, जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों को कर देता है बर्बाद : मुख्यमंत्री

वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विकास यात्रा में युवा शक्ति रचनात्मक भूमिका निभा रही है। सभी नागरिक भी विकासात्मक गतिविधियों से स्वयं को जोड़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति समाज की विकास यात्रा पर कुठाराघात करती है। मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नशा मुक्त मध्यप्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। नशे से लड़ाई में पूरा देश एकजुट है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने हर तरह के नशे पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत की है। नशा, नाश की जड़ है, जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देता है। नशे से सभी प्रकार की रचनात्मकता और आगे बढ़ने की संभावनाओं पर कुठाराघात होता है, वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होते हैं। नशा परिवारों को बर्बाद कर देता है। राज्य सरकार ने अपनी समस्त क्षमताओं के साथ प्रदेशवासियों के सहयोग से नशे के खिलाफ अभियान आरंभ किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से नशा मुक्त मध्यप्रदेश अभियान में हरसंभव सहयोग प्रदान करने और अभियान को समर्थन देने का आव्हान किया है।

राज्य सरकार प्रदेशवासियों के सहयोग से नशे के विरूद्ध अभियान में होगी सफल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नशामुक्त भारत के संकल्प तथा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह के वर्ष 2029 तक भारत को पूर्णतः नशामुक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस दिशा में जनभागीदारी के साथ निरंतर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सलवाद जैसी बड़ी लड़ाई में भी विजय प्राप्त की है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के सहयोग से नशे के विरूद्ध अभियान में भी सफल होगी।

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जाएगा अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बाबा महाकाल हमारे साथ हैं, हम नशामुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण में सफल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी प्रदेशवासियों और युवाओं से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 15 से 30 जुलाई तक चलाए जाने वाले नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान से जुड़ने का आहवान किया।

ताजुल मसाजिद के बाहर वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन

काली पट्टी बांधकर निकले नमाजी, दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के विरोध में पोस्टर लेकर पहुंचे

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के विरोध में शुक्रवार को राजधानी भोपाल की ताजुल मसाजिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तस्वीर वाले पोस्टर लेकर नियुक्ति को वापस लेने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हालांकि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और पुलिस की मौजूदगी में संपन्न हुआ।

पोस्टरों पर लिखे थे विरोध के संदेश- प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले पोस्टर थे, जिन पर लिखा था कि वक्फ संशोधन कानून के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जहां वक्फ बोर्ड में

दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है। पोस्टरों पर नॉन मुस्लिमों की एंट्री बैन करे, वक्फ में तानाशाही नहीं चलेगी और वक्फ हमारी आस्था का केंद्र है, इसमें सदैव मुस्लिम ही रहेंगे जैसे संदेश भी लिखे थे।

नमाज पढ़ने आया था, विरोध देखकर शामिल हो गया- प्रदर्शन में शामिल अब्बास खान ने बताया कि वह नियमित रूप से जुमे की नमाज अदा करने ताजुल मसाजिद पहुंचे थे। नमाज के बाद बाहर निकलने पर विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिली तो वह भी उसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए दोनों गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाए और पहले की तरह बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य ही रहें।

सरकार पर लगाए भेदभाव के आरोप

प्रदर्शन में शामिल माज़ कुरैशी ने आरोप लगाया कि सरकार एकतरफा फैसले ले रही है। उनका कहना था कि यदि सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है तो मुस्लिम समाज को भी विभिन्न संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ से जुड़े फैसलों के माध्यम से मुस्लिम समाज की धार्मिक संस्थाओं और संपत्तियों को प्रभावित किया जा रहा है।

पूर्व आईएएस नियाज खान बोले-

मुस्लिम पहनावा बदलें,तुर्की जैसे कपड़े पहनने की सलाह, ट्विट में लिखा- इससे मॉब लिंचिंग से बचेंगे

भोपाल (नप्र)। एमपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी और लेखक नियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने लिखा कि भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाओं से बचने के लिए मुस्लिमों को अपना पहनावा बदलकर तुर्की के मुसलमानों जैसा पहनावा अपनाना चाहिए, ताकि उनकी पहचान आसानी से न हो सके। नियाज खान ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत में मॉब लिंचिंग के ज्यादातर मामलों में पीड़ित कुर्ता, पायजामा, दाढ़ी और टोपी पहने हुए थे। उनका कहना है कि इस पहनावे से उनकी पहचान

आसानी से हो जाती है। इसलिए मुस्लिमों को अपना ड्रेस और हुलिया बदल लेना चाहिए।

लोकतंत्र पर भी उठाए सवाल- एक अन्य पोस्ट में नियाज खान ने लोकतंत्र पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि कई आजाद देशों ने लोकतंत्र तो अपनाया, लेकिन उसके मूल सिद्धांत नहीं अपनाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र के नाम पर नेता और अफसर जमकर पैसा लूटते हैं, जबकि जनता मुफ्त की सुविधाओं में व्यस्त रहती है।

भौतिकवाद और राजनीति पर भी पोस्ट- 9 जुलाई को किए गए अन्य पोस्ट में नियाज खान ने लिखा कि भौतिकवाद ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम और ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के चुने जाने से लोकतंत्र कमजोर होता है।

जीतू पटवारी का भाई बोला- 3 साल पहले ड्रग्स लेता था

कांग्रेस अध्यक्ष का भाई होना ही मेरी गलती, इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया था

इंदौर (नप्र)। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस हिरासत में लेने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। पार्टी इसे सियासी एंगल देने के मूड में है। शुक्रवार को जीतू और नाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।

इस दौरान नाना पटवारी ने स्वीकार किया कि वे 3 साल पहले तक ड्रग्स का सेवन करते थे, लेकिन रिहैब सेंटर में इलाज के बाद उन्होंने नशा पूरी तरह छोड़ दिया है। उन्होंने कहा- मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं जीतू का भाई हूं। वहीं, जीतू ने कहा- राज्य सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बना रही है। नाना का ड्रग तस्करी मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्हें हिरासत में लेकर परेशान किया गया।

दरअसल, इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने गुरुवार को नाना पटवारी को हिरासत में लिया था। पुलिस का दावा है कि ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए दो आरोपियों से पूछताछ में नाना का नाम सामने आया था। हालांकि, पूछताछ के बाद देर रात उन्हें छोड़ दिया गया था।

गिरफ्तार लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं

नाना पटवारी ने कहा कि उनकी गलती केवल इतनी है कि वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई हैं। उन्होंने दावा किया कि ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों से उनका कोई संबंध या लेन-देन नहीं है। नाना ने बताया कि वे अपनी कार की सर्विसिंग कराने गए थे, तभी पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। थाने में उनसे केवल नाम पूछा गया और हिरासत में लेने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। उनका आरोप है कि पुलिस पूरे दिन उन्हें शहर में इधर-उधर घुमाती रही और देर रात छोड़ दिया। नाना पटवारी ने बताया कि उनकी गाड़ी संजय कौशल उर्फ रॉनी के सर्विस सेंटर में धुलती है। यहां गोलू भी काम करता है। पुलिस ने उनसे संजय कौशल और इरफान के बारे में पूछताछ की, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और चुनाव में काम कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस स्कॉर्पियो वाहन की चर्चा हो रही है, वह संजय कौशल उर्फ रॉनी की है और उसमें मिले किसी भी सामान से उनका कोई संबंध नहीं है।

तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार के पॉवर

48 लाख ग्रामीणों को मुफ्त रजिस्ट्री देने रेवेन्यू अफसरों को अधिकार, अब जल्द होगी कार्यवाही

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में आबादी की भूमि पर काबिज 48 लाख से अधिक परिवारों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने राज्य सरकार ने तहसीलदारों, प्रभारी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार के पॉवर दिए हैं।

इसके साथ ही रजिस्ट्री पर लगने वाले पंचायत उपकर की राशि अब सरकार खुद पंचायतों को देगी। इसके लिए भी सरकार ने कैबिनेट से ऐसे मामले में पंचायत उपकर माफ करने की मंजूरी दे दी है।

मोहन यादव सरकार ने 2 जून को हुई कैबिनेट बैठक में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के अंतर्गत स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। इससे सरकार पर 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार

आने वाला है।

इसके लिए राज्य सरकार के पंजीयन और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने अलग-अलग अध्यादेश के नोटिफिकशन जारी कर दिए हैं। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत उपकर के रूप में ली जाने वाली राशि ऐसे मामलों में माफ किए जाने और पंजीयन विभाग ने पंजीयन व मुद्रांक शुल्क माफ किए जाने का नोटिफिकेशन किया है। ताजा मामला तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार के पॉवर दिए जाने से संबंधित है जिसके लिए पंजीयन और मुद्रांक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिन ग्रामीणों को आबादी भूमि की रजिस्ट्री मुफ्त कराकर देना है उस भूमि की रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय में सब रजिस्ट्रार तो करेंगे ही, साथ ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार और प्रभारी तहसीलदार भी रजिस्ट्री कर सकेंगे। इससे संबंधित लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश में 235 सब रजिस्ट्रार के अलावा राजस्व न्यायालय का काम देखने वाले ये अधिकारी भी रजिस्ट्री कर सकेंगे।

संपादकीय

पंजाब : कांग्रेस में गुटबाजी थमेगी?

पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी गुट की बगावत कांग्रेस हाईकमान के दबाव के बाद थम गई है, ऐसा मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। इसे तूफान के पहले की शांति भी माना जा सकता है, क्योंकि चन्नी गुट भाजपा के संपर्क में भी बताया जाता है, लेकिन भाजपा ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी, शायद इसलिए भी चन्नी ने हथियार डालना ही उचित समझा। गुटबाजी और अंतर्कलह कांग्रेस का राजरोग है। यह बात अलग है कि पार्टी उसे इसे अपना 'आंतरिक लोकतंत्र' बताती है। लेकिन वहां लोकतंत्र और अराजकता में खास फर्क नहीं है। चूंकि पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस की सत्ता में लौटने की संभावना है, ऐसे में पार्टी के कई नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के मुंह खोल दिए हैं। चूंकि चरणजीत सिंह चन्नी को पिछली बार दलित कार्ड के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर राज्य का सीएम बनाया गया था, लेकिन चुनाव में वो कोई कमाल नहीं कर पाए और खुद भी दोनों सीटों से हार गए थे। हालांकि बाद में वो लोकसभा चुनाव जीत गए थ। तब से उनके मन में फिर से राज्य का सीएम बनने की महत्वाकांक्षा जोर मार रही है। यह बात उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक कर के जता दी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चन्नी चाहते हैं कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि चुनाव जीतने की स्थिति में वो राज्य के सीएम पद की दावेदारी कर सकें। शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस हाईकमान उनके दबाव में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा चन्नी को ही सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि हाईकमान जो रणनीति बनाएगा, हम मिलकर साथ चलेंगे। इस बीच कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने दावा किया कि है कि सभी नाराज नेता जल्द एकजुट हो जाएंगे। बताया जाता है कि चन्नी ने इसके पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चरणजीत चन्नी से फोन पर बात की थी। यह भी तय हुआ कि चन्नी गुट के दो नेता भूपेश बघेल से मिलेंगे। इसके बाद चन्नी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। वहीं भूपेश बघेल पूर्व मंत्री ब्रह्म महेंद्र को मनाने पहुंचे है। चन्नी के झुकने के पीछे कारण यह भी है कि उन्होंने पहले दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी या उनकी टीम से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें किसी ने टाइम नहीं दिया। चन्नी के अपने खेमे में सात विधायक और एक सांसद बताए जाते हैं। लेकिन मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर राजा वंडिंग के साथ 23 जिलो के प्रदेशाध्यक्ष बताए जाते हैं। इस बीच चन्नी गुट के समर्थक विधायक परगट सिंह ने कहा कि हम पंजाब में इस वक्त एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। उनका निशाना हाल ही में हाईकमान द्वारा नियुक्त किए गए तीन नए कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्षों पर था। परगट ने कहा कि हमारे बीच मतभेद हो सकता है लेकिन हम सभी कांग्रेसियों का मकसद पंजाब में आम आदमी पार्टी और भाजपा द्वारा बनाई जा रही रणनीति को ध्वस्त करना है। हालांकि अगर सब एकजुट रहे तो चन्नी के साथ हो रहे व्यवहार से दलित वोट बैंक पर असर का डर देख हाईकमान उनसे मुलाकात कर सकता है। इसी बीच पंजाब कांग्रेस की बगावत पर भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने तंज कसते हुए कहा है कि भूपेश बघेल का बयान कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी तानाशाही, वंशवादी राजनीति और चापलूसी वाली कार्यप्रणाली को साफ तौर पर दिखाता है। बहरहाल हाईकमान के इस फैसले ने राजा वडिंग के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में लीड करने का रास्ता साफ कर दिया है।

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप'
लेखक स्तंभकार हैं।

शांति की उम्मीदों के बीच फिर युद्ध के बादल

विश्व व्यवस्था का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब पश्चिम एशिया अशांत हुआ है, तब-तब उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। आज एक बार फिर यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, इज़राइल- ईरान संघर्ष, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य की सुरक्षा पर मंडराते खतरे और समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ते हमलों ने वैश्विक समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। हाल के घटनाक्रमों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी जवाबी कार्रवाई तथा अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने जैसी घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम एशिया अभी भी स्थायी शांति से बहुत दूर है। यह केवल दो देशों का टकराव नहीं, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि इस पूरे संकट को उसके ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संदर्भों में समझा जाए।

पश्चिम एशिया सदियों से सभ्यताओं का संगम रहा है। यही क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों का केंद्र भी है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल और अन्य खाड़ी देशों की सामरिक स्थिति उन्हें वैश्विक राजनीति का केंद्र बना देती है। यही कारण है कि अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देशों की विदेश नीति में पश्चिम एशिया हमेशा विशेष स्थान रखता है। ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आतंकवाद, धार्मिक मतभेद तथा क्षेत्रीय प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र को लगातार अस्थिर बनाए रखती है। आज का संकट भी इन्हीं जटिल परिस्थितियों की उपज है।

अमेरिका और ईरान के संबंध 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा और इज़राइल के प्रति दोनों देशों की विपरीत नीतियाँ समय-समय पर संघर्ष का कारण बनती रही हैं। यद्यपि कई बार वार्ता और समझौतों के माध्यम से तनाव कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल सका। वर्तमान घटनाक्रम इसी लंबे संघर्ष का नया अध्याय है, जिसने पूरे क्षेत्र को फिर से अस्थिरता की ओर धकेल दिया है।

हालिया घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों पक्ष प्रत्यक्ष युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी जारी रखना चाहते हैं। ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाना और अमेरिका द्वारा उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करना इस बात का संकेत है कि अविश्वास की खाई पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी है। यदि यह संघर्ष और आगे बढ़ता है तो इसमें इज़राइल, हिज़्बुल्लाह, हूती विद्रोही तथा अन्य क्षेत्रीय संगठन भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह केवल दो देशों का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया व्यापक युद्ध की चपेट में आ सकता है।

पश्चिम एशिया के संकट का सबसे संवेदनशील पक्ष हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य है। विश्व के समुद्री मार्ग से होने वाले कच्चे तेल के बड़े हिस्से का परिवहन इसी रास्ते से होता है। यदि किसी कारण से यह मार्ग बंद होता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो तेल की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। इसका प्रभाव केवल तेल उत्पादक देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा आयात करने वाले सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य की सुरक्षा आज वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है।

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ते ही सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता दिखाई देती है। निवेशक जोखिम वाले क्षेत्रों से पूंजी निकालने लगते हैं, जिससे शेयर बाजारों में गिरावट आती है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से परिवहन महँगा हो जाता है। उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। महँगाई का दबाव बढ़ने से आम नागरिक की क्रय शक्ति घटती है। विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती है और सरकारों के सामने राजकोषीय संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि पश्चिम एशिया का कोई भी संकट वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन जाता है।

भारत के लिए पश्चिम एशिया केवल एक पड़ोसी क्षेत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग इसी क्षेत्र से आयात करता है। यदि तेल की कीमतों में वृद्धि होती है, तो इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, परिवहन, कृषि और उद्योगों पर पड़ेगा। महँगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख से अधिक भारतीय कार्यरत हैं। यदि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनकी सुरक्षा, रोजगार और भारत को भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय निर्यात और समुद्री व्यापार भी प्रभावित होंगे। इसलिए भारत के लिए यह संकट केवल विदेश नीति का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आज विश्व अर्थव्यवस्था वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर आधारित है। पश्चिम एशिया से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्ग एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते हैं। यदि इन मार्गों पर असुरक्षा बढ़ती है, तो जहाजों की आवाजाही धीमी हो जाती है, बीमा लागत बढ़ जाती है और माल ढुलाई महँगी हो जाती है। इसका प्रभाव खाद्यान्न, उर्वरक, मशीनरी, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। इस प्रकार एक क्षेत्रीय संघर्ष पूरी दुनिया के व्यापारिक तंत्र को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी आवश्यकता युद्ध नहीं, बल्कि संवाद की होती है। संयुक्त राष्ट्र, जी-20, यूरोपीय संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली का प्रयास करें। केवल आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई किसी भी विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। यदि बातचीत के रास्ते खुले रहेंगे, तभी शांति की संभावना बनी रहेगी। भारत सहित कई देश लगातार यह संदेश देते रहे हैं कि सभी विवादों का समाधान कूटनीति और वार्ता के माध्यम से ही संभव है।

भारत ने हमेशा 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति अपनाई है। भारत के अमेरिका, ईरान, इज़राइल और खाड़ी देशों, सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। यही संतुलित दृष्टिकोण उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भारत किसी भी पक्ष का समर्थन करने के बजाय शांति, संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन की वकालत करता है। साथ ही भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने और आयात के स्रोतों में विविधता लाने पर भी लगातार कार्य कर रहा है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति केवल युद्धविराम से संभव नहीं होगी। इसके लिए सभी देशों को परस्पर विश्वास बढ़ाना होगा, क्षेत्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना होगा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना होगा। यदि विकास, व्यापार और जनकल्याण को प्राथमिकता दी जाए तो संघर्ष की संभावनाएँ स्वतः कम होंगी। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी ताकि किसी भी विवाद को समय रहते सुलझाया जा सके।

पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता आज केवल क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, इज़राइल- ईरान संघर्ष, ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितता और समुद्री व्यापार पर मंडराता खतरा पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह चुनौती और भी गंभीर है क्योंकि उनकी आर्थिक प्रगति वैश्विक स्थिरता से जुड़ी हुई है। इसलिए समय की मांग है कि शक्ति प्रदर्शन के स्थान पर संवाद, प्रतिशोध के स्थान पर विश्वास और युद्ध के स्थान पर शांति को प्राथमिकता दी जाए। इतिहास यह सिद्ध करता है कि युद्ध केवल विनाश देता है, जबकि संवाद और सहयोग ही मानव सभ्यता को स्थायी विकास, समृद्धि और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाते हैं। पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना केवल उस क्षेत्र की आवश्यकता नहीं, बल्कि पूरे विश्व की साझा जिम्मेदारी है।

खेल विश्व

डॉ. सुधीर सक्सेना
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

केप वर्डे, फुटबॉल और वोजिन्हा

केप वर्डे छोटा-सा देश है। आबादी और क्षेत्रफल, दोनों के मान से छोटा। क्षेत्रफल कुल जमा 4,033 वर्ग किमी और जनसंख्या पाँच लाख से थोड़ा ऊपर। भारत के मँझोले शहर भी इससे अधिक आबादी को अपनी परिधि में समेटे हुए हैं। कल तक इसे लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन फीफा प्रतियोगिता में उसके जाँबाज प्रदर्शन से उसका नाम सबकी जुबान पर आ गया। उसने जिस तरह से फीफा में प्रवेश की पात्रता अर्जित की और फिर मैदान पर जिस चपलता से गेंद पर नियंत्रण की कला दर्शायी, उसने लाखों खेल-प्रेमियों को उसका और विशेषकर गोलकीपर वोजिन्हा का मुरीद बना दिया।

केप वर्डे (पुर्तगाली में केबो वर्दे) की यह बसाहट भी ज्यादा पुरानी नहीं है। पंद्रहवीं शती में जब यूरोप के राष्ट्रों में नए-नए समृद्धि मार्ग खोजने और दौलत कमाने की धुन सवार हुई, तब सदी के पूर्वार्द्ध में पुर्तगाली जहाज इधर से गुजरे। नौवहन के मान से इसकी अवस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। पुर्तगालियों ने ट्रांस-एटलांटिक क्षेत्र में इस निर्जन द्वीप-समूह की अहमियत को बूझ लिया। जून 1444 में इसका नामकरण हुआ केबो वर्दे। वर्ष 1462 से पुर्तगालियों ने यहाँ विधिवत बसना शुरू किया। शुरूआत हुई सांतियागो से। हाथीदाँत, रेशम, गरम मसालों, कपड़े और रम के व्यापार में जहाजों की आवाजाही, ईंधन और डेरे के लिहाज से यह जगह माकूल थी। रही-सही कसर दास-व्यापार ने पूरी कर दी। अफ्रीकी गुलामों से भरे जलपोत इधर से होकर गुजरते। इससे द्वीप-समूह मालामाल हुआ। मिंडोल आदर्श पत्तन बनकर उभरा। समृद्धि ने जलदस्युओं को भी आकर्षित किया। वर्ष 1585 में अंग्रेज जलदस्यु फ्रांसिस ड्रेक ने इसे लूटा और करीब सवा सौ साल बाद, सन् 1712 में, इस पर फ्रांसीसियों ने हमला किया। जब तक दास-प्रथा रही, केप वर्डे फलता-फूलता रहा। दास-प्रथा समाप्त हुई तो इसकी समृद्धि को ग्रहण लग गया। लेकिन अब तक यह पश्चिम की नजरों में चढ़ चुका था।

सन् 1832 में दो बड़ी घटनाएँ घटीं। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के दूत की हैसियत से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को जाते हुए एडमंड रॉबर्ट्स यहाँ आए। दूसरे, एचएमएस बीगल पर सवार वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने भी यहाँ कुछ दिन गुजारे। तब इसकी हैसियत पुर्तगाल के उपनिवेश की थी। अफ्रीका के पश्चिमी तट से करीब 450 किमी दूर मध्य एटलांटिक महासागर में स्थित इस लघु द्वीप-समूह के विकास में लिस्बन की कोई दिलचस्पी न थी। फलतः स्थानीय जनों में सुगबुगाहट हुई। जब आजादी की माँग बलवती हुई तो पुर्तगाल ने इसे अपने उपनिवेश के बजाय समुद्रपारीय प्रांत घोषित कर दिया। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। सन 1956 में अमीलकार कब्राल ने आजादी के लिए अहिंसक संघर्ष के ऐलान के साथ पार्टी का गठन किया। मकसद था गिनी और केप वर्डे की पुर्तगाल से मुक्ति। गिनी तो आजाद हो गया, लेकिन केप में दमन बढ़ गया। इससे सशस्त्र संघर्ष को हवा मिली। सन् 1973 में कब्राल की हत्या हो गई और सन् 1974 में लिस्बन में कू-दे-ता। द्वीप-समूह के करीब दस हजार वालंटियरों ने करीब 35 हजार पुर्तगाली और अफ्रीकी सैनिकों से करीब चौदह साल तक लोहा लिया। एमीकार के सौतेले भाई लुईस कब्राल ने संघर्ष की कमान संभाली। अंततः जुलाई, सन् 1975 में केप वर्डे आजाद हुआ। संप्रति केप वर्डे में निर्वाचित सरकार है और प्रेया उसकी राजधानी। समूह के दस में से नौ द्वीपों में बस्तियाँ हैं, एक अभी भी निर्जन है। जून 2014 में बराक ओबामा यहाँ सपत्निक आए थे। यहाँ की 80 प्रतिशत आबादी कैथोलिक है और दस प्रतिशत प्रोटेस्टेंट। केप वर्डे तितलियों, गुबरैलों और पतंगों की दुर्लभ प्रजातियों तथा मत्स्य-व्यंजनों के लिए मशहूर है। यहाँ की बेअरफुट गायिका सिसारिया एवोरा के लोग मुरीद हैं। लोग पुर्तगाली या क्रियोल बोलते हैं। केप वर्डे आज चमकीले सफेद रेत के समुद्री तटों, तेज संगीत, बारहमासी धूप और मिश्रित संस्कृति के लिए जाना जाता है।

बिलाशक फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है और राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को ब्लू शार्क के नाम से जाना जाता है। कौन यकीन करेगा कि ब्लू शार्क ने अपना पहला फुटबॉल मैच 19 अप्रैल, सन् 1978 में गिनी के खिलाफ खेला था। पहले ही मैच में हार के बाद टीम ने जी-तोड़ मेहनत की। सन् 2010 में जोआओ डी डेउस कोच बने। उन्होंने डायस्पोरा से खिलाड़ी चुनकर टीम का कायाकल्प कर दिया। सन् 2013 और सन् 2023 में टीम अफ्रीकी कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुँची। सन 1986 में फीफा की सदस्य बनी केप वर्डे की टीम की सन् 2000 में रैंकिंग 182 थी। अपने संकल्प और खेल के जरिये वह फीफा 26 की रैंकिंग में 67वें स्थान पर आ गई। इसके बाद फीफा विश्व कप में जो कुछ हुआ, वह सबके सामने है।

शुक्रवार, दो जुलाई को मियामी में अर्जेंटीना से केप वर्डे का मुकाबला हुआ तो अखबारों में सुर्खियाँ थीं– 'वोजिन्हा वर्सेज मेसी।' कहाँ 4.8 करोड़ की आबादी का दूसरा विशालतम लैटिन अमेरिकी राष्ट्र अर्जेंटीना और कहाँ बित्ते भर का केप वर्डे। मगर साइप्रस, हंगरी और यूएई के खिलाफ टीम के धमाल ने कमाल कर दिया था। 1.89 मीटर कद के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा (जो सीमाऊ जोसे एवोरा डायस) ने गोलरक्षक के तौर पर जो अचूक प्रदर्शन किया था, उसने उन्हें सबकी आँख का तारा और प्रशंसा का पात्र बना दिया था। केप वर्डे अर्जेंटीना से अतिरिक्त समय में 3-2 से हार गया, लेकिन केप ने करोड़ों फुटबॉल-प्रेमियों का दिल जीत लिया।

मैच की समाप्ति के बाद वोजिन्हा मेसी के पास गया। वोजिन्हा के शब्दों में, 'मेसी ने मुझे आगोश में लिया और कहा– 'यू आर ग्रेट। आपके लोगों को आप पर फख्र होना चाहिए।' यह मेरे लिए अविश्वसनीय था। उसका यह कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मैंने कहा– 'थैंक यू, लियो। यू आर ग्रेट।'

जानते हैं, उसके बाद क्या हुआ? वोजिन्हा ने मेसी से इल्तजा की– 'क्या हम अपनी कमीजें बदल सकते हैं?'मेसी ने कहा– 'हाँ, क्यों नहीं। बस, इंटरव्यू के बाद।'

इसके दो दिन बाद ही केप वर्डे की टीम लौट आई। प्रेया हवाई अड्डे पर हजारों केपवर्डियनों ने टीम का भावभीना स्वागत किया। वहाँ कार्निवाल जैसा दृश्य था। वोजिन्हा अगले फीफा विश्व कप में शायद न खेल सके, लेकिन आज की तारीख में उस छोटे-से देश का बड़ा खिलाड़ी है।

सुविधा के साथ मानवीय सोच की परीक्षा

एआई का दौर

संध्या अग्रवाल
लेखक साहित्यकार हैं।

तकनीक ने मानव जीवन को हमेशा नई दिशा दी है। पहिए के आविष्कार से लेकर इंटरनेट और स्मार्टफोन तक, हर परिवर्तन ने जीवन को सरल बनाया है। आज हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। यह केवल कंप्यूटर की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि और संचार जैसे अनेक क्षेत्रों में तेजी से अपनी जगह बना रही है।

एआई ने कई कामों को आसान बना दिया है। अब बड़ी मात्रा में उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण कुछ ही क्षणों में किया जा सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में रोगों की पहचान और उपचार की योजना बनाने में सहायता मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए सीखने के नए माध्यम उपलब्ध हुए हैं और व्यवसायों में काम करने की गति बढ़ी है। निश्चित रूप से एआई मानव की क्षमता को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है।

लेकिन हर सुविधा के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या तकनीक के बढ़ते प्रभाव के बीच मानव अपनी मौलिक सोच और संवेदनशीलता को बनाए रख पाएगा? मशीन सूचनाओं के आधार पर उत्तर दे सकती है, लेकिन उसमें मानवीय अनुभव, भावनाएं और नैतिक समझ नहीं होती। किसी निर्णय में केवल जानकारी नहीं, बल्कि विवेक और संवेदना की भी आवश्यकता होती है। आज कई लोग छोटे-छोटे कामों के लिए भी पूरी तरह तकनीक पर निर्भर होते जा रहे हैं। इससे सोचने, विश्लेषण करने और स्वयं समाधान खोजने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए यह जरूरी है कि वे एआई को ज्ञान बढ़ाने और कार्यक्षमता सुधारने का माध्यम बनाएं, न कि अपनी रचनात्मकता का विकल्प।

रोजगार के क्षेत्र में भी एआई को लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं। कुछ पारंपरिक कार्यों में बदलाव संभव है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर तकनीकी परिवर्तन नए अवसर भी लेकर आता है। आवश्यकता इस बात की है कि लोग समय के अनुसार अपने कौशल को विकसित करें और नई तकनीकों को समझकर उनका सही उपयोग करें।

एआई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है। यदि इसका प्रयोग शिक्षा को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है तो यह मानव विकास का मजबूत साधन बन सकता है। लेकिन यदि इसका उपयोग गलत सूचनाएं फैलाने, लोगों को भ्रमित करने या मानवीय संबंधों को कमजोर करने के लिए किया गया तो इसके परिणाम चिंताजनक हो सकते हैं।

हमें यह समझना होगा कि तकनीक मानव के लिए है, मानव तकनीक के लिए नहीं। मशीनें हमारी सहायता कर सकती हैं, लेकिन जीवन के मूल मूल्य–विश्वास, करुणा, सहयोग और जिम्मेदारी–केवल मानव ही निभा सकता है। भविष्य का समाज वह नहीं होगा जहां मशीनें मनुष्यों का स्थान ले लें, बल्कि वह होगा जहां मानव अपनी बुद्धि और संवेदना के साथ तकनीक का बेहतर उपयोग करे। एआई के इस दौर में असली परीक्षा मशीनों की नहीं, बल्कि हमारी मानवीय सोच की है।

तकनीक को अपनाना समय की आवश्यकता है, लेकिन अपनी मानवीय पहचान को बनाए रखना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम सुविधा और संवेदना के बीच संतुलन बना पाए तो एआई मानव सभ्यता के लिए वरदान साबित हो सकता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'
लेखक व्यंग्यकार हैं।

खुशी मुफ्त थी, हमने उसका कोर्स खरीद लिया

आज के भारत में हर समस्या से पहले उसका प्रशिक्षक मिल जाता है। देश अब कृषि प्रधान या युवा प्रधान नहीं, बल्कि कार्यशाला प्रधान लगता है। पहले आदमी के पास समस्या होती थी, अब उससे पहले कार्यशाला का पोस्टर पहुँच जाता है। कहीं 'जीवन बदलने का बूटकैंप', कहीं 'खुश रहने की मास्टरक्लास', तो कहीं 'सकारात्मक सोच का महाशिविर'। लगता है, भगवान ने मनुष्य को अधूरा बनाया और उसे पूरा करने का ठेका प्रशिक्षकों, मोटिवेशनल गुरुओं और लाइफ कोचों को दे दिया हो। अब हालत यह है कि आदमी अपनी अक्ल पर कम और किसी न किसी कार्यशाला की रसीद पर ज़्यादा भरोसा करने लगा है।

पिछले सप्ताह पार्क में एक परिचित मिले। चेहरे की चमक देखकर लगा, अभी-अभी आत्मज्ञान की किस्त भरकर लौटे हैं। मुस्कराकर बोले, 'अभी 'जीवन को सहज बनाने' की कार्यशाला पूरी की है। अब न क्रोध आता है, न तनाव होता है, और हर शब्द सोच-समझकर निकलता है।' तभी पत्नी का फोन आ गया। अगले ही पल उनकी आवाज़ पूरे पार्क में गूँज रही थी–'इतनी-सी बात भी याद नहीं रहती? दूध फ्रिज में रखना था!' फोन रखते ही सहज होकर बोले, 'कल 'क्रोध पर विजय' का एडवांस कोर्स है... चलोगे?' तब समझ आया, हमारे यहाँ क्रोध नहीं जाता, बस उस पर होने वाली कार्यशालाओं का स्तर बढ़ता जाता है।

घर का झाड़ू-पोछा हमें बोझ लगता है, लेकिन वही पसीना बहाने के लिए जिम की फीस भर देते हैं। घर में सीढ़ियाँ चढ़ना भारी पड़ता है, जिम की मशीन पर बीस मिनट चढ़ना फिटनेस कहलाता है। पहले लोग कुएँ से पानी भरते, खेतों में काम करते, पैदल बाजार जाते थे; अलग से व्यायाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब दिन भर कुर्सी पर बैठकर कमर खराब कीजिए, फिर पैसे देकर वही कमर योग गुरु के सामने झुकाइए। घर तक पैदल चलना अपमान लगता है, ट्रेडमिल पर चलना उपलब्धि। अब योग भी ऑनलाइन है। गुरुजी कहते हैं, 'गहरी साँस लीजिए।' इधर कैमरा बंद है, उधर शिष्य चाय की चुस्की ले रहा है। योग खत्म, और फेसबुक पर पोस्ट–'आज आत्मा से जुड़ने का दिव्य अनुभव।'

अब हमारी समस्याएँ घर में नहीं सुलझतीं, बाजार में सुलझाई जाती हैं। बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा? 'डिजिटल पैरेंटिंग मास्टरक्लास' कर लीजिए। उधर बच्चा दरवाज़े से पुकारता है–'मम्मी, मेरे साथ खेलो।' इधर जवाब आता है–'अभी नहीं बेटा, मैं सीख रही हूँ कि बच्चों के साथ समय कैसे बिताया जाता है।' पति-पत्नी में बात बंद हो तो दोनों अलग-अलग 'रिलेशनशिप कोच' के पास पहुँच जाते हैं। पहले दो कप चाय में बात बन जाती थी, अब चार वेबिनार और छह पीडीएफ चाहिए। लगता है, रिश्ते अब दिल से नहीं, पावरपॉइंट की स्लाइडों से चलेंगे।

एक बार मैं भी 'समय प्रबंधन' की कार्यशाला में जा पहुँचा। प्रशिक्षक ने कहा, 'हर मिनट अनमोल है, समय ही जीवन है।' कार्यशाला खत्म होते ही वही लोग दो घंटे प्रमाणपत्र के साथ सेल्फियाँ खिंचवाते रहे। घर पहुँचकर व्हाट्सऐप स्टेटस लगाया–'आज समय का सही उपयोग करना सीखा।' पत्नी ने पूछा, 'क्या सीखा?' मैंने कहा, 'समय बचाना।' बोली, 'तो पहले रसोई के बर्तन धो दीजिये, मेरा भी समय बच जाएगा।' उसी दिन समझ आया कि कार्यशालाओं की असली परीक्षा एयरकंडीशंड हॉल में नहीं, घर की रसोई में होती है।

इस कारोबार का पहला नियम है–पहले आपको यक़ीन दिलाओ कि आपमें कोई न कोई कमी ज़रूर है। कमी न मिले तो नई बता दो–आप पर्याप्त सकारात्मक नहीं हैं, सजग नहीं हैं, उत्पादक नहीं हैं या आध्यात्मिक नहीं हैं। फिर उसी कमी का कोर्स बेच दो। कोर्स पूरा होते-होते जेब हल्की, दीवार पर नया सर्टिफिकेट और मन में यह सुखद भ्रम कि अब जीवन बदल गया। सच तो यह है कि जीवन नहीं बदलता, सिर्फ़ दीवार पर टँगे सर्टिफिकेट बढ़ जाते हैं।

आजकल अनुभव से बड़ा परिचय 'सर्टिफाइड' होना है। शर्मा जी कल तक बैंक में क्लर्क थे, आज 'अंतरराष्ट्रीय लाइफ कोच' हैं। मैंने पूछा, 'इतना ज्ञान कहाँ से मिला?' बोले, 'बीस कार्यशालाएँ कर चुका हूँ।' मैंने सोचा, जिनकी सलाह बच्चे नहीं मानते, वे फीस लेकर बच्चों का भविष्य सँवार रहे हैं। जिनके घर रोज़ महाभारत होती है, वे बाहर 'सुखी परिवार' पर व्याख्यान देते हैं। एक सकारात्मक सोच वाले गुरु को पत्नी ने घर से निकाल दिया। अगले हफ्ते विज्ञापन आया–'नकारात्मक परिस्थितियों को अवसर में बदलने का प्रशिक्षण।' हमारे यहाँ हर असफलता अगली कार्यशाला का विज्ञापन बन जाती है।

मुझे लगता है, एक दिन आदमी यमराज से भी कहेगा–'प्रभु, अभी मत ले जाइए। पहले 'मृत्यु को सहज स्वीकारने' की प्रमाणित कार्यशाला पूरी कर लूँ। बिना सर्टिफिकेट स्वर्ग में प्रवेश कैसे मिलेगा?' यमराज कहेंगे—'तुम्हें जीवन दिया था जीने के लिए, हर पल की तैयारी करने के लिए नहीं।' जीने के लिए किसी कार्यशाला की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा घर का काम कर लेते, अपनों के साथ बैठ लेते, हँस लेते, गलतियों से सीख लेते—यही जीवन का असली पाठ था। बाकी सब केवल जीवन की तैयारी थी, जीवन नहीं।' जीवन को बेहतर बनाने की दौड़ में हम उसे जीना ही भूल गए हैं। खुशियाँ कार्यशालाओं में नहीं, अपनों की मुस्कान, रिश्तों की गर्माहट और छोटे-छोटे पलों में छिपी होती हैं। अंत में सर्टिफिकेट नहीं, केवल जिए हुए रिश्ते और यादें साथ जाती हैं।

फीफा विश्व कप

ममता कुशवाहा

लेखक स्तंभकार हैं।

खेल महाकुंभ की पर्यावरणीय चुनौती

फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, सपनों और उत्साह का प्रतीक है। विश्व कप जैसे आयोजनों के दौरान पूरा विश्व एक साझा उत्सव में डूब जाता है। लेकिन खेलों की चमक-दमक और उत्साह के पीछे एक ऐसा पक्ष भी छिपा है, जिस पर लंबे समय तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। यह पक्ष है पर्यावरण पर पड़ने वाला उसका प्रभाव। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2026 में आयोजित फीफा विश्व कप अब तक का सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला विश्व कप बन सकता है। यह चेतावनी केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक खेल आयोजनों और उनके पर्यावरणीय प्रभावों पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है।

वर्तमान समय में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है। कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप है, कहीं बाढ़ और चक्रवात तबाही मचा रहे हैं, तो कहीं जंगलों में आग लाखों हेक्टेयर भूमि को निगल रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया, तो पृथ्वी का भविष्य और अधिक संकटग्रस्त हो जाएगा। ऐसे समय में जब प्रत्येक क्षेत्र से पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जा रही है, तब खेल जगत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। खेलों के विशाल आयोजन, जिनमें लाखों दर्शक और हजारों खिलाड़ी शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं। वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में चल रहा है। यह पहली बार होगा जब विश्व कप में 48 टीमें भाग लेंगी। पहले की तुलना में अधिक टीमें, अधिक मैच और अधिक शहर इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। कुल 16 शहरों में 104 मैच खेले जाएंगे। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, अधिकारियों, पत्रकारों और दर्शकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करनी होगी। यही वह प्रमुख कारण है जिसके चलते कार्बन उत्सर्जन में भारी वृद्धि की आशंका व्यक्त की जा रही है।

कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत हवाई यात्रा होती है। विश्व कप जैसे आयोजनों में लाखों लोग विमानों के माध्यम से हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। जब टीमें एक देश से दूसरे देश और एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, तब ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ता है। वर्ष 2026 के इस विश्व कप में तीन देशों के अनेक शहरों को मेजबानी दी गई है। इससे यात्राओं की दूरी और संख्या दोनों में वृद्धि होगी। यही कारण है कि शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आयोजन पर्यावरणीय दृष्टि से अब तक का सबसे भारी विश्व कप साबित हो सकता है। दरअसल, खेल आयोजनों का पर्यावरणीय प्रभाव केवल यात्रा तक सीमित नहीं होता। स्टेडियमों के निर्माण और रखरखाव में भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। विशाल स्टेडियमों को रोशन करने, वातानुकूलित रखने, सुरक्षा व्यवस्था संचालित करने और प्रसारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारी बिजली की आवश्यकता होती है। यदि यह ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त हो रही है, तो उसका सीधा संबंध कार्बन उत्सर्जन से जुड़ जाता है। इसके अतिरिक्त भोजन, पेय पदार्थ, प्लास्टिक सामग्री, विज्ञापन और अन्य व्यवस्थाओं में भी पर्यावरणीय लागत शामिल होती है।

आज खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है। यह एक विशाल वैश्विक उद्योग बन चुका है। अरबों डॉलर के निवेश, प्रायोजन और व्यावसायिक हित इसके साथ जुड़े हुए हैं। फुटबॉल क्लब, प्रसारण कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां खेल आयोजनों को एक बड़े आर्थिक अवसर के रूप में देखती हैं। लेकिन जब आर्थिक लाभ पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर हावी होने लगता है, तब समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। यही चिंता शोधकर्ताओं ने भी व्यक्त की है कि फुटबॉल का बढ़ता व्यावसायीकरण और आयोजनों का निरंतर विस्तार पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। आज कल जलवायु परिवर्तन का प्रभाव खेलों पर भी पड़ रहा है। बढ़ता तापमान खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है। कई देशों में अत्यधिक गर्मी के कारण मैचों का समय बदलना पड़ा है। कुछ स्थानों पर मौसम की अनिश्चितता के कारण प्रतियोगिताओं को स्थगित करना पड़ा। वर्षा, तूफान और गर्म हवाएं खेल आयोजनों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। अर्थात् जिस जलवायु संकट को खेल उद्योग अनजाने में बढ़ा रहा है, वही संकट अब खेलों के अस्तित्व के लिए भी खतरा बनता जा रहा है।

वैज्ञानिक आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बना देते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति से पहले यह स्तर लगभग 280 पीपीएम था, जबकि आज यह 430 पीपीएम से अधिक पहुंच चुका है। यह वृद्धि केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि पृथ्वी के बदलते पर्यावरण का संकेत है। बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र को अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने की आवश्यकता है। फुटबॉल और अन्य खेल संगठनों ने हाल के वर्षों में पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं की घोषणाएं अवश्य की हैं। कई संगठनों ने कार्बन न्यूट्रल बनने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने की योजनाएं प्रस्तुत की हैं। कुछ स्टेडियम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। यदि आयोजन लगातार बड़े और अधिक विस्तृत होते जाएंगे, तो पर्यावरणीय लाभ सीमित रह जाएंगे।

इस तरह भविष्य के खेल आयोजनों के लिए एक नई सोच की आवश्यकता है। आयोजकों को ऐसे मॉडल अपनाने होंगे जिनमें यात्रा की दूरी कम हो, स्थानीय संसाधनों का अधिक उपयोग हो और नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाए। दर्शकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्टेडियमों के निर्माण में पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का प्रयोग बढ़ाना होगा। साथ ही आयोजनों के आकार और विस्तार को लेकर भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि खेल जगत अपनी लोकप्रियता का उपयोग पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए करे। फुटबॉल खिलाड़ियों और खेल सितारों का प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ता है। यदि वे जलवायु संरक्षण का संदेश देंगे, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन भी बन सकता है।

फीफा विश्व कप 2026 को लेकर उठी कार्बन उत्सर्जन की चिंता हमें एक व्यापक सच्चाई की ओर संकेत करती है। विकास, मनोरंजन और आर्थिक प्रगति आवश्यक हैं, लेकिन उनकी कीमत प्रकृति के विनाश के रूप में नहीं चुकाई जा सकती। पृथ्वी हमारी साझा विरासत है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। खेलों का उत्सव तभी सार्थक होगा जब वह मानवता को जोड़ने के साथ-साथ प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता को भी मजबूत करे। आज आवश्यकता इस बात की है कि खेलों की चमक के साथ पर्यावरणीय चेतना का प्रकाश भी उतना ही प्रखर हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ, संतुलित और सुरक्षित पृथ्वी पर अपने सपनों का खेल खेल सकें।

इतिहास में दफन सच, सत्ता की हिंसा और स्मृति के प्रतिरोध की फिल्म

सतलुज

डॉ. नरेश गौतम

सहायक प्रोफेसर श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर

यह कहानी केवल पंजाब के उग्रवाद के दौर की कहानी नहीं है बल्कि यह उस दौर के राज्य-सत्ता,पुलिस, प्रशासन और आम नागरिक के बीच टूटते विश्वास की कहानी है। यह बताती है कि जब सत्ता अपने अस्तित्व को बचाने या अपनी जीत साबित करने में अंधी हो जाती है, तो वह कानून, न्याय और मानवाधिकारों की सीमाएँ कितनी आसानी से पार कर देती है। फिल्म की आत्मा का सबसे बड़ा आधार हैं जसवंत सिंह खालड़ा, वह मानवाधिकार कार्यकर्ता, जिन्होंने पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान हजारों अज्ञात और लापता लोगों के गुप्त अंतिम संस्कार का पर्दाफाश किया। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड, श्मशानों के रजिस्टर और दस्तावेज़ों के आधार पर यह प्रश्न उठाया कि जिन लोगों को अज्ञात बताकर जला दिया गया, वे आखिर थे कौन? उनकाअपराध क्या था? उनके परिवार कहाँ थे? यही प्रश्न उन्हें अंततः अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। उनकी हत्या स्वयं इस बात का प्रतीक बन गई कि कई बार सबसे बड़ा अपराध बन जाता है इतिहास में जलियांवाला बाग नरसंहार को ब्रिटिश औपनिवेशिक दमन का सबसे भयावह प्रतीक माना जाता है।

किसी भी समाज का सबसे बड़ा संकट तब शुरू होता है, जब इतिहास केवल विजेताओं द्वारा लिखा जाने लगता है और मृतकों की आवाज़ को भी सत्ता अपने हिसाब से तय करने लगती है। 'सतलुज' ऐसी ही फिल्म है,जो उस दौर के पंजाब की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक को पर्दे परलाने का साहस करती है। यही कारण है कि यह फिल्म 3 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज़ हुई और महज़ दो दिन बाद, 5 जुलाई को ओटीटीसे हटा दी गई। किसी फिल्म का इतनी जल्दी गायब हो जाना केवल एक तकनीकी घटना नहीं,बल्कि यह भी सवाल है कि आखिर ऐसी कौन-सी बेचैनी थी, जिससे कुछ लोग इतने असहज हो उठे?

यह कहानी केवल पंजाब के उग्रवाद के दौर की कहानी नहीं है बल्कि यह उस दौर के राज्य-सत्ता,पुलिस, प्रशासन और आम नागरिक के बीच टूटते विश्वास की कहानी है। यह बताती है कि जब सत्ता अपने अस्तित्व को बचाने या अपनी जीत साबित करने में अंधी हो जाती है, तो वह कानून, न्याय और मानवाधिकारों की सीमाएँ कितनी आसानी से पार कर देती है।फिल्म की आत्मा का सबसे बड़ा आधार हैं जसवंत सिंह खालड़ा, वह मानवाधिकार कार्यकर्ता, जिन्होंने पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान हजारों अज्ञात और लापता लोगों के गुप्त अंतिम संस्कार का पर्दाफाश किया। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड, श्मशानों के रजिस्टर और दस्तावेज़ों के आधार पर यह प्रश्न उठाया कि जिन लोगों को अज्ञात बताकर जला दिया गया, वे आखिर थे कौन? उनका अपराध क्या था? उनके परिवार कहाँ थे? यही प्रश्न उन्हें अंततः अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। उनकी हत्या स्वयं इस बात का प्रतीक बन गई कि सच बोलना कई बार सबसे बड़ा अपराध बन जाता है इतिहास में जलियांवालाबाग नरसंहार को ब्रिटिश औपनिवेशिक दमन का सबसे भयावह प्रतीक माना जाता है। लेकिन पंजाब के उग्रवाद काल की त्रासदी का दर्द अलग प्रकार का था। यहाँ आरोप यह रहे कि अपने ही लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर, अपने ही नागरिकों का एक बड़ा वर्ग संदेह, भय और उग्रवाद की व्यापक परिभाषा के बीच पिसता चला गया। हजारों लोग लापता हुए, अनेक कथित फर्जी मुठभेड़ों की कहानियाँ सामने आईं और वर्षों तक अनेक परिवार अपने प्रियजनों का अंतिम सत्य भी नहीं जान सके। इतिहास के वे पन्ने आज भी पूरी तरह पढ़े नहीं गए हैं। वे अब भी सवालों और खूनी स्मृतियों से भरे हुए हैं। 'सतलुज' पंजाब पुलिस और बेगुनाह पंजाबियों की मौतों के बीच उलझी हुई उसी डोर को सामने रखती है, जिसका सिरा आज भी पूरी तरह किसी के हाथ में नहीं है। फिल्म किसी एक पक्षका महिमा मंडन नहीं करती, बल्कि उस भय, अविश्वास और हिंसा को चित्रित करती है जिसने पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म देखते हुए बार-बार यह विचार आता है कि जिस समय ये घटनाएँ घट रही थीं, उस समय इन पर लिखना ही असाधारण साहस का काम रहा होगा। क्या उस दौर की निरंकुश शक्तियों ने कभी कल्पना की होगी कि एक दिन इन्हीं घटनाओं पर फिल्म बनेगी? कि एक दिन उनके फैसलों, उनके अभियानों और उनके अपराधों पर सार्वजनिक बहस होगी?

इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यही है वह देर से बोलता है, लेकिन चुप हमेशा नहीं रहता। आज भी जब कथित मुठभेड़ों, बुलडोज़र राजनीति, राज्य की असाधारण शक्तियों और मानवाधिकारों पर बहस होती है, तब असहमति व्यक्त करना आसान नहीं होता। लेकिन इतिहास गवाही देता है कि कोई भी दौर स्थायी नहीं होता। आज जिन प्रश्नों को दबा दिया जाता है, वही कल शोध, साहित्य, सिनेमा और जनस्मृति का विषय बनते हैं। सत्ता का हर निर्णय इतिहास में उसी रूप में दर्ज नहीं होता, जैसावह स्वयं चाहती है। कहा जाता है कि लाशें कभी झूठ नहीं बोलतीं। कोई भी शव वास्तव में लावारिस नहीं होता, क्योंकि समय स्वयं हर मृतक का सबसे बड़ा वारिस होता है। देर-सबेर सच दस्तावेज़ों, स्मृतियों,गवाहियों के माध्यम से लौटता है। जो लोग आज अन्याय को न्याय समझते हैं, इतिहास अक्सर उन्हें अलग कतार में खड़ा करता है। इसीअर्थ में 'सतलुज' केवल एक फिल्म नहीं,बल्कि स्मृति का प्रतिरोध है।

यह हमें याद दिलाती है कि शांति यदि न्याय के बिना स्थापित की जाए, तो वह केवल भय का दूसरा नाम होती है। किसी भी लोकतंत्र में कानून का शासन तभी सार्थक है, जब वह निर्दोषों की रक्षा करे, यदि कानून स्वयं भय का औजार बन जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा खत्म हो जाती है। फिल्म पर प्रतिबंध लगना भी अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। किसी रचना से असहमति हो सकती है, उसके तथ्यों पर बहस हो सकती है, उसकी व्याख्या पर आलोचना हो सकती है, लेकिन किसी फिल्म को सार्वजनिक विमर्श से हटाना अक्सर जिज्ञासा और संदेह दोनों को और बढ़ा देता है। विचारों का उत्तर प्रतिबंध नहीं, बल्कि तर्क,शोध और खुली बहस होना चाहिए। इस फिल्म का सबसे प्रभावशाली पक्ष इसका अभिनय, निर्देशन और वातावरण रचना है। कैमरा केवल दृश्य नहींदिखाता, बल्कि भय, खामोशी और असुरक्षा का मनोविज्ञान भी रचता है। जसवंत सिंह खालड़ा जैसे चरित्रों की स्मृति फिरजीवित हो उठती है और वे प्रश्न दोबारा हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जिन्हें इतिहास ने सुविधानुसार पीछे धकेल दिया था। इतिहास का अनुभव केवल पंजाब तक सीमित नहीं है। दुनिया के लगभग हर समाज में ऐसेदौर आए हैं,जब राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास गहरे स्तर पर टूट गया। समय बीतने के बाद उन्हीं घटनाओं पर किताबें लिखी गईं न्यायिक आयोग बने, दस्तावेज़ सार्वजनिक हुए और फिल्में बनीं। इसलिए यह मान लेना कि कोई सच हमेशाके लिए दफन रह जाएगा, इतिहास को न समझने जैसा है। 'सतलुज' हमें एकअसुविधाजनक लेकिन अत्यंत आवश्यक प्रश्न पूछने के लिए विवश करती हैक्या शांति के नाम पर किया गया अन्याय वास्तव में शांति ला सकता है? उत्तर शायद नहीं है। क्योंकि अन्याय कभी स्थायी शांति की नींव नहीं बन सकता। भय से कुछ समय के लिए सन्नाटा तो स्थापित किया जा सकता है, लेकिन न्याय के बिना स्थायी शांति संभव नहीं होती। न्याय में देर हो सकती है, लेकिन स्मृतियों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। पंजाब की त्रासदी अपने समय और परिस्थितियों में वीभत्स थी, लेकिन उसके उठाए गए प्रश्न केवल पंजाब तक सीमित रहते हैं बल्कि आज भी जब हम देश के विभिन्न हिस्सों की ओर देखते हैं,तो राज्य, सुरक्षा, मानवाधिकार और न्याय के वही कठिन प्रश्न हमारे सामने खड़े दिखाई देते हैं।

नक्सलवाद या माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों छत्तीसगढ़, ओडिशा,महाराष्ट्र, तेलंगाना तथाअन्य राज्यों में दशकों से सुरक्षा अभियानों और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कोलेकर गंभीर बहस होती रही है। अलग-अलग समय पर फर्जी मुठभेड़ों, हिरासत में मौतों, लापता व्यक्तियों और निर्दोष नागरिकों के प्रभावित होने जैसे आरोप भी सामने आते रहे हैं। यही बात उत्तर-पूर्व, विशेषकर मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर भी लागू होतीहै, जहाँ हिंसा, असुरक्षा और प्रशासनिक विफलताओं ने अनेक कठिन प्रश्न खड़े किए हैं। घटनाओं के स्वरूप अलग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं,लेकिन लोकतंत्र में मूल प्रश्न वही रहता है क्या कानून केशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना न्याय संभव है? 'सतलुज' फिल्म की सबसे बड़ीउपलब्धि यही है कि वह किसी एक घटना का पुनर्निर्माण भर नहीं करती, बल्कि हमारे समय से भी संवाद करती है। वह हमें याद दिलाती है कि जब राज्य की शक्ति असाधारण हो जाती है,तब उसके साथ असाधारण जवाबदेही भी आवश्यक होती है। अन्यथा इतिहास बार-बार उन्हीं सवालों के साथ लौटता है। निर्देशक हनी तेहरान ने इस विषय को पर्दे परलाकर उल्लेखनीय साहस का परिचय दिया है। जिस विषय पर दशकों तक खामोशी, भय और विवाद का माहौल बना रहा हो, उसे सिनेमा केमाध्यम से सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाना आसान नहीं होता। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में ऐसी फिल्मों का मूल्य केवल उनकी सिनेमाई गुणवत्ता से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि वे हमें इतिहास के कठिन प्रश्नों का सामना करने का साहस देती हैं। क्योंकि इतिहास को भुला देने से इतिहास समाप्त नहीं होता वह स्मृतियों,दस्तावेज़ों और कला के माध्यम से बार-बार लौटता है।

क्या मनुष्य केवल एक संख्या है?

विश्व जनसंख्या दिवस

रविकान्त राऊत

लेखक स्तंभकार हैं।

11 जुलाई को जब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तब समाचारों और सरकारी अभियानों में बार-बार कुछ परिचित वाक्य सुनाई देते हैं–'बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है', 'छोटा परिवार सुखी परिवार', 'जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है।' परंतु इन नारों के बीच एक प्रश्न अक्सर अनसुना रह जाता है–क्या वास्तव में समस्या जनसंख्या है, या हम मनुष्य को केवल एक संख्या में बदल देने के अभ्यस्त हो गए हैं?

किसी राष्ट्र की जनसंख्या केवल गिनती नहीं होती। वह उसकी श्रमशक्ति है, उसकी सृजनात्मक ऊर्जा है, उसका भविष्य है, उसकी संस्कृति है और उसका सामूहिक स्वप्न भी है। यही जनसंख्या यदि शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर हो तो वही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूँजी बन जाती है; और यदि वह अशिक्षा, कुपोषण, बेरोज़गारी और असमानता से घिर जाए, तो वही संख्या एक बोझ प्रतीत होने लगती है। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस हमें केवल लोगों की गिनती करने का नहीं, बल्कि मनुष्य के सम्मान और उसके जीवन की गुणवत्ता पर विचार करने का अवसर देता है।

विश्व जनसंख्या दिवस की पृष्ठभूमि भी रोचक है। 11 जुलाई 1987 को अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी की जनसंख्या पाँच अरब के आँकड़े तक पहुँच गई है। इसे 'फ़ाइव बिलियन डे' कहा गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 1989 में निर्णय लिया कि हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। 1990 से इसका औपचारिक आयोजन प्रारंभ हुआ। उद्देश्य स्पष्ट था, परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच संतुलन के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित करना।

किन्तु इतिहास बताता है कि जनसंख्या पर चिंता नई नहीं है। अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने भविष्यवाणी की थी कि जनसंख्या ज्यामितीय गति से बढ़ेगी जबकि खाद्यान्न उत्पादन उससे बहुत पीछे रह जाएगा। उनके अनुसार अकाल, महामारी और युद्ध प्रकृति के ऐसे साधन हैं जो जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। यह विचार लंबे समय तक नीति-निर्माताओं को प्रभावित करता रहा।

परंतु बाद के विचारकों ने माल्थस से असहमति भी व्यक्त की। उनका तर्क था कि समस्या जनसंख्या नहीं, बल्कि संसाधनों का असमान वितरण है। आज भी संसार में जितना भोजन उत्पादित होता है, वह पूरी मानवता की आवश्यकता से कम नहीं है; फिर भी करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। दूसरी ओर, विकसित देशों में प्रतिवर्ष लाखों टन भोजन नष्ट कर दिया जाता है। यदि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण न हो, तो कम जनसंख्या वाला समाज भी अभावग्रस्त हो सकता है, और यदि व्यवस्था सुचारु हो तो अधिक जनसंख्या वाला देश भी समृद्ध बन सकता है। यहीं से विश्व जनसंख्या दिवस का विमर्श केवल जन्मदर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीति और सत्ता तक पहुँच जाता है।

इतिहास साक्षी है कि हर संगठित राज्य ने अपनी जनता की गिनती की है। जनगणना केवल आँकड़ों का संग्रह नहीं थी; उसके आधार पर कर वसूले गए, सेनाएँ गठित हुईं, श्रम का नियोजन हुआ और शासन की नीतियाँ बनाई गईं। आधुनिक लोकतंत्रों में भी जनसंख्या का प्रत्येक आँकड़ा योजनाओं, बजट, निर्वाचन क्षेत्रों, सामाजिक कल्याण और आर्थिक नीतियों का आधार बनता है। इसलिए जनसंख्या शासन का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। इक्कीसवीं सदी में यह प्रक्रिया और सूक्ष्म हो गई है। आज नागरिक केवल जनगणना की सूची में

दर्ज नाम नहीं है; वह डिजिटल पहचान, बैंकिंग, मोबाइल, सामाजिक मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से निरंतर आँकड़ों में परिवर्तित होता जा रहा है। उसकी पसंद, उसकी यात्रा, उसकी खरीदारी, उसके विचार और यहाँ तक कि उसके व्यवहार के पैटर्न भी डेटा बन चुके हैं। पहले राजा अपनी प्रजा की संख्या जानना चाहता था; आज एल्गोरिद्म नागरिक के व्यवहार को पढ़ना चाहते हैं। प्रश्न यह नहीं कि यह व्यवस्था आवश्यक है या नहीं; प्रश्न यह है कि क्या इस प्रक्रिया में मनुष्य कहीं केवल एक डेटा-बिंदु बनकर तो नहीं रह गया?

फिर भी जनसंख्या को केवल नियंत्रण के दृष्टिकोण से देखना भी एक भूल होगी। भारत इसका जीवंत उदाहरण है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, पर यही जनसंख्या यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक कौशल और स्वास्थ्य सेवाओं से संपन्न हो जाए, तो यही हमारी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकती है। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है। इसके विपरीत जापान और यूरोप के अनेक देश घटती जनसंख्या और वृद्ध होती आबादी की चुनौती से जूझ रहे हैं। चीन ने कभी एक-संतान नीति अपनाई थी; आज वही देश अधिक बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या का प्रश्न स्थिर नहीं, बल्कि समय, समाज और अर्थव्यवस्था के अनुसार बदलता रहता है।

भारत के संदर्भ में इस विषय का एक और आयाम है, अंत्योदय। किसी भी नीति की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि राष्ट्रीय आँकड़े कितने सुंदर दिखते हैं, बल्कि इस बात से कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आया। उसके लिए जनसंख्या का अर्थ किसी सरकारी रिपोर्ट का प्रतिशत नहीं, बल्कि स्कूल में बच्चे की सीट, अस्पताल में उपलब्ध बिस्तर, खेत के लिए पानी, रोज़गार का अवसर और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की संभावना है। यदि ये उपलब्ध नहीं हैं, तो केवल जनसंख्या को दोष देना वास्तविक समस्या से ध्यान हटाना है।

इसलिए परिवार नियोजन को भी केवल जनसंख्या नियंत्रण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अनुभव बताता है कि जहाँ महिलाओं की शिक्षा बढ़ती है, वहाँ जन्मदर स्वाभाविक रूप से घटती है। जहाँ बाल विवाह कम होते हैं, वहाँ परिवार छोटे होते हैं। जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर होती हैं, वहाँ माता-पिता को अनेक बच्चों की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अर्थात् जनसंख्या संतुलन किसी दमनकारी नीति का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा और समान अवसरों का स्वाभाविक प्रतिफल है।

आज विश्व एक नए मोड़ पर खड़ा है। एक समय भय था कि पृथ्वी पर मनुष्य बहुत अधिक हो जाएँगे; अब अनेक देशों को चिंता है कि भविष्य में काम करने वाले लोग पर्याप्त नहीं होंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और बदलती अर्थव्यवस्था इस बहस को और जटिल बना रहे हैं। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस का संदेश अब केवल 'जनसंख्या घटाइए' नहीं रह गया है; बल्कि 'जनसंख्या को सक्षम बनाइए' होना चाहिए।

आखिरकार किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी जनसंख्या की संख्या में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की गुणवत्ता में निहित होती है। भूखे, अशिक्षित और निराश लोगों की भीड़ किसी देश को महान नहीं बनाती; शिक्षित, स्वस्थ, स्वतंत्र और संवेदनशील नागरिक ही उसे सभ्य बनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि मनुष्य केवल एक आँकड़ा नहीं है। जब उसे केवल संख्या माना जाता है, तब नीतियाँ उसे गिनती हैं; जब उसे नागरिक माना जाता है, तब संविधान उसे अधिकार देता है; और जब उसे मनुष्य माना जाता है, तब सभ्यता उसे सम्मान देती है। शायद इस दिवस का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आने वाले समय में हमें जनसंख्या नहीं, बल्कि मनुष्यता का संतुलन बनाए रखना होगा।

नगर की सफाई व्यवस्था चौपट ,बिना कचरा गाड़ी कैसे सफाई हो : पार्षद धर्मदास बैलबंशी

सोहागपुर। इंदिरा वार्ड के वरिष्ठ पार्षद धर्मदास बैलबंशी ने आरोप लगाया है कि नगर में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। आपने यह भी कहा कि सफाई कर्मचारी बिना कचरा गाड़ी के सफाई कर्मचारी सफाई भी कैसे करें। वर्तमान समय में नगर सफाई व्यवस्था चौपट होने से मच्छर एवं अन्य जीव जंतुओं का प्रकोप भी बढ़ रहा है। श्री बेलबशी ने यह भी आरोप लगाया है कि नगर पंचायत परिषद में सत्ता से जुड़े कुछ नुमाइंदों का बेवजह का हस्तक्षेप करना इस नगर पंचायत परिषद को भारी पड़ रहा है। इस कारण अध्यक्ष महोदया एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि उनके कार्य में सहयोग करने वाले उनके पति स्वतंत्र रूप से नगर पंचायत परिषद का संचालन करने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।

वर्नतमान में नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। सफाई कर्मियों के पास कचरा उठाने के लिए हाथ कचरा गाड़ी नहीं है। सफाई कर्मचारियों के पास सुरक्षा साधन जैसे ग्लब्स,मास्क आदि भी नही है। एक के ऊपर एक आधा दर्जन मुकद्दम तैनात कर दिए है। इसके उलट पिपरिया,होशंगाबाद की बड़ी नगर पालिकाओं में एक सेनेटरी इंस्पेक्टर एवं एक या दो मुकद्दम ही सारे नगर की सफाई व्यवस्था संभाल रहे है। लेकिन हमारी छोटी सी नगर पंचायत परिषद में कोटे से मुकद्दम नियुक्त है। श्री बेलबशी ने सत्ता पक्ष के नगर पंचायत परिषद में हस्तक्षेप कर्ताओं से निवेदन किया है। कि नगर विकास में आप नगर पंचायत परिषद एवं अध्यक्ष का सहयोग करे । तथा अनुचित हस्तक्षेप नहीं करे। आपने अंत में आरोप लगाया है कि वर्तमान समय में नगर पंचायत परिषद में हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है। कि अध्यक्ष नगर के पन्द्रह वार्डो के लिए 15 कचरा गाड़ी खरीदने में भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। पार्षद धर्मदास बैलबंशी ने सभी सत्ता पक्ष के हस्तक्षेपकर्ताओं से निवेदन है कि जिस तरह कांग्रेस के सभी पांचों पार्षद नगर विकास में नगर पंचायत परिषद के संचालन में सहयोग कर रहे है ।आप भी नगर की जनता-जनार्दन के कार्यों में सहयोग करें। ताकि नगर विकास में बांधा उत्पन्न न हो।

बार-बार वॉशरूम जाने पर भड़के रीवा कमिश्नर

मीटिंग रोककर सबका करवाया शुगर टेस्ट, 16 अधिकारियों का लेवल 200 के पार

मैहर (नप्र)। मध्यप्रदेश के मैहर जिला मुख्यालय में गुरुवार को विभिन्न शासकीय विभागों की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान एक बेहद अजीबोगरीब और अनोखा वाकया सामने आया। बैठक ले रहे रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने जब देखा कि समीक्षा के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी बार-बार उठकर वॉशरूम (शौचालय) जा रहे हैं, तो वे अपनी नाराजगी रोक नहीं पाए।

बार-बार क्यों जा रहे हैं बाहर?

रीवा कमिश्नर ने तल्ख लहजे में टोकते हुए पूछा आप लोग बार-बार बाहर क्यों भाग रहे हैं, शुगर पेशेंट हैं क्या? बात सिर्फ टोकने तक ही सीमित नहीं रही। कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए बैठक में ही मौजूद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला को तत्काल कड़े निर्देश दिए कि मीटिंग में मौजूद हर एक अधिकारी और कर्मचारी का ऑन-स्पॉट ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाए।

बैठक कक्ष के बाहर बना ग्लूकोमीटर सेंटर

कमिश्नर का फरमान मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सिविल अस्पताल मैहर के पैरामेडिकल स्टाफ को मेडिकल किट के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष बुलाया गया। बैठक कक्ष के ठीक बाहर ही ग्लूकोमीटर के साथ एक विशेष जांच शिविर स्थापित कर दिया गया। एक-एक करके बैठक में मौजूद सभी 49 अधिकारियों और कर्मचारियों की उंगलियां पंच कर ब्लड शुगर की रैंडम जांच की गई।

मंत्री सारंग ने की नरेला विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

नरेला विधानसभा बनेगी देश की सबसे स्वच्छ विधानसभा

भोपाल। सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को मंत्रालय में नरेला विधानसभा अंतर्गत शहीद भगत सिंह, स्वामी विवेकानन्द, सुभाष एवं सम्राट अशोक मंडल के पदाधिकारियों तथा नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मंत्री श्री सारंग ने मंडल अंतर्गत सभी वार्डों में जलभराव, पेयजल आपूर्ति, ड्रेनेज व्यवस्था, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, स्वच्छता तथा विद्युत आपूर्ति सहित नागरिकों से जुड़े सभी मूलभूत विषयों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्ड का विस्तृत सर्वेक्षण कर समस्याओं का

आकलन किया जाए तथा समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उनका त्वरित, प्रभावी एवं स्थायी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक नागरिक तक सरकार की सुविधाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुँचना चाहिए।

नरेला विधानसभा बनेगी देश की सबसे स्वच्छ विधानसभा- बैठक में मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा को देश की सबसे स्वच्छ विधानसभा के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि जनभागीदारी का व्यापक आंदोलन है। इसके लिए विधानसभा के प्रत्येक वार्ड, गली और मोहल्ले में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जाएगा। नगर निगम, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों के सहयोग से नरेला को स्वच्छता के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।

समस्त वार्डों में होगी मातृ-पितृ सेवा केंद्र की स्थापना- मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में मातृ-पितृ सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन सेवा केंद्रों में वरिष्ठजनों के लिए मनोरंजन एवं मानसिक सक्रियता बढ़ाने वाली लाइब्रेरी, कैरम, शतरंज, फिटनेस संबंधी सहित विभिन्न गतिविधियां उपलब्ध होंगी। जिससे वे अपने समय का सदुपयोग, अपने अनुभव साझा कर सकें और समाज की नई पीढ़ी को अपने ज्ञान एवं संस्कारों से प्रेरित कर सकें।

हितेश बीजेपी आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक बने

गिरजेश बने सह संयोजक, ओबीसी मोर्चा के चार जिलाध्यक्ष और 3 संभागीय कार्यालय मंत्री भी बनाए

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश भाजपा ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए आईटी विभाग, संभागीय कार्यालय मंत्री, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा में कई पदों पर नियुक्तियां की हैं। आईटी विभाग में उज्जैन के हितेश नागदेव को प्रदेश संयोजक बनाया गया है।

भोपाल के गिरजेश तिवारी (आशु) को संगठनात्मक डेटा प्रबंधन एवं तकनीकी नवाचार का सह संयोजक नियुक्त किया गया है।

तीन संभागों के कार्यालय मंत्री नियुक्त किए

प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन की ओर से जारी आदेश में ग्वालियर संभाग का कार्यालय मंत्री कोमल पचेया, रीवा संभाग का कार्यालय मंत्री वीरेश पाण्डेय और जबलपुर संभाग का कार्यालय मंत्री राजेश मिश्रा को बनाया गया है।

ओबीसी मोर्चा के 4 जिलाध्यक्ष घोषित

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने चार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। इनमें मऊगंज से आनंद साहू, श्योपुर से श्रीधर गुर्जर, सिवनी से रविशंकर पाल और इंदौर नगर से निखिल सोनी को जिम्मेदारी दी गई है।

एसटी मोर्चा के दो जिला अध्यक्ष नियुक्त

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह टेकाम ने रीवा जिले का अध्यक्ष सी.एल. रावत और डिंडौरी का अध्यक्ष संदीप टेकाम को नियुक्त किया है।

आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा दोस्त का साथ

संकट में देख 50 फीट गहरे कुएं में बचाने उतरा, जहरीली गैस ने दोनों की ले ली जान

बालाघाट (नप्र)। जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र के पिपरटोला गांव में एक दर्दनाक हादसे में दो दोस्तों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों कुएं में लगी मोटर सुधारने के लिए उतरे थे। पहले एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी तो उसे बचाने के लिए दूसरा दोस्त भी कुएं में उतर गया, लेकिन वह भी जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो गया। करीब पांच घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद एसडीईआरएफ की टीम ने दोनों के शव बाहर निकाले।

जानकारी के अनुसार पिपरटोला निवासी महेश चौधरी (45) गुरुवार शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच अपने दोस्त युवराज बिसेन (55) के घर के पीछे स्थित लगभग 50 फीट गहरे कुएं में खराब मोटर सुधारने के लिए उतरे थे। कुएं के भीतर मौजूद जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी हालत अचानक बिगड़ गई।

महेश को संकट में देखकर उनके दोस्त युवराज बिसेन उन्हें बचाने के लिए बिना देर किए कुएं में उतर गए, लेकिन वे भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। देखते ही देखते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।

5 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही किरनापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुएं में जहरीली गैस होने की आशंका के चलते तत्काल बालाघाट से एसडीईआरएफ की टीम बुलाई गई। रेस्क्यू अभियान के दौरान एसडीईआरएफ के जवान करण सिंह वल्के ऑक्सीजन सिलेंडर और सुरक्षा मास्क पहनकर करीब 50 फीट गहरे कुएं में उतरे। रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच रस्सियों की सहायता से दोनों शवों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

आज होगा अंतिम संस्कार

किरनापुर थाना प्रभारी राजकुमार चौधरी ने बताया कि दोनों शवों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

रेस्क्यू टीम की रही अहम भूमिका

रेस्क्यू अभियान में थाना प्रभारी राजकुमार चौधरी, होमगार्ड एएसआई महेश कुमार सहित एसडीईआरएफ के हवलदार सुनील कुमार नागपुरे, सैनिक संजय चौधरी, सतीश तोमर, करण सिंह वल्के, विशाल रजक, आशीष खरोले, राजेश धुर्वे और चेतेश्वर राहंगडाले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह हादसा एक बार फिर बिना सुरक्षा उपकरण और गैस की जांच किए कुओं में उतरने के खतरों की याद दिलाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंद और गहरे कुओं में ऑक्सीजन की कमी तथा जहरीली गैसों की मौजूदगी जानलेवा साबित हो सकती है।

50 हजार रिश्वत लेने के बाद भी सीना तानकर दिखा रहा था हेकड़ी

लोकायुक्त गिरफ्त में आते ही ठंडे पड़े तेवर, सिर झुकाए बैठा रहा

आगर मालवा (नप्र)। एमपी के आगर मालवा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय में दबिश देकर लोकायुक्त की टीम ने सहायक ग्रेड-3 और प्रभारी लेखपाल मनीष कुमार पंडया को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाबू एक सेवानिवृत्त अधिकारी के लंबित पड़े 27 लाख रुपये के भुगतानों को पास करने के एवज में डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था।

पिता के फंड के लिए बेटे से मांगी थी रिश्वत

जानकारी के अनुसार, रतलाम के जावरा में रहने वाले विजय कुमार बोरसिया ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त से की थी। विजय के पिता गोवर्धन लाल आगर के जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी ग्रेच्युटी, बीमा और अवकाश नकदीकरण जैसी मदों के करीब 27 लाख रुपये का भुगतान काफी समय से अटका हुआ था। इसी राशि को जारी करने के नाम पर बाबू मनीष कुमार पंडया लगातार डेढ़ लाख रुपये की डिमांड कर रहा था।

लोकायुक्त ने ऐसे बिछाया जाल

परेशान होकर पीड़ित के बेटे ने 8 जुलाई को लोकायुक्त एसपी आनंद कुमार यादव से लिखित शिकायत की। लोकायुक्त ने मामले की गोपनीय जांच निरीक्षक दीपक सेजवार से कराई, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद जाल बिछाकर गुरुवार, 10 जुलाई को शिकायतकर्ता को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये देकर आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही बाबू मनीष कुमार पंडया ने दफ्तर में रिश्वत की रकम पकड़ी, पहले से तैयार बैठी लोकायुक्त की 10 सदस्यीय टीम ने उसे दबोच लिया। लोकायुक्त की टीम ने मौके पर ही नोट जब्त कर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई दल में डीएसपी दिनेशचंद पटेल, निरीक्षक दीपक सेजवार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

लोकायुक्त की जनता से अपील, जारी किए नंबर

कार्रवाई के बाद लोकायुक्त संगठन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो डरे नहीं। नागरिक तुरंत लोकायुक्त उज्जैन के मोबाइल नंबर 9425103975 या लैंडलाइन नंबर 0734-2512756 पर इसकी सूचना देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अभियान में सहयोग कर सकते हैं।

उफनती नदी के बीच आदिवासियों का चिता आंदोलन

कहा- प्रशासन ने पानी की सप्लाई बंद की, कई बीमार पड़े

छतरपुर (नप्र)। केन बेतवा लिंक परियोजना में मुआवाजे की मांग को लेकर आदिवासियों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश की सरकार ने बुधवार को 202.5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दे दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस महिलाओं, बच्चों और बुजर्गों को नदी का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पानी पीने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए हैं। उन्होंने अधिकारियों पर उनकी शिकायतों को दूर करने के बजाए उन्हें डराने-

धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ये लोग पन्ना से हैं और जिला अधिकारियों से उनसे मिलने के लिए कहा गया है। अब कुछ भी बाकी नहीं है। उनकी सभी मांगें पूरी कर ली गई हैं।

पात्र परिवारों को मिलेंगे 12.5 लाख रुपए मिलेंगे एकमुश्त- इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने मझगवां, रुंज और केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्टस से विस्थापित परिवारों के लिए एक विशेष पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज के तहत पात्र परिवारों को 12.5 लाख रुपए तक एकमुश्त पुनर्वास अनुदान मिलेगा।

कदम से विस्थापन के डर और मुआवजे की उनकी मांगों का समाधान नहीं है। साथ ही विरोध जारी रखने का संकल्प लिया है।

सातवें दिन भी प्रदर्शन जारी- बारिश के बीच नदी उफान पर है लेकिन आदिवासी महिला और पुरुषों का प्रदर्शन सातवें दिन भी जारी है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और मझगवां, रुंज, नेगुवा और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स से विस्थापित आदिवासी और किसान छतरपुर में अपना जल सत्याग्रह जारी रखे हुए हैं।

पानी की सप्लाई रोक दी- प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने विरोध स्थल पर पीने के पानी की सप्लाई रोक दी है, जिससे

विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: कॉल सेंटर सेवाओं का विस्तार

1912 के साथ-साथ नया संपर्क नंबर 0755-4314165 शुरू

भोपाल। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक, त्वरित एवं निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कॉल सेंटर सेवाओं का विस्तार किया है। उपभोक्ताओं की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त SIP चैनल जोड़े गए हैं। साथ ही एयरटेल नेटवर्क के माध्यम से नया संपर्क नंबर 0755-4314165 भी प्रारंभ किया गया है। अब उपभोक्ता बीएसएनएल के टोल-फ्री नंबर 1912 के अतिरिक्त 0755-4314165 पर भी कॉल कर विद्युत आपूर्ति, बिल एवं स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायत दर्ज कराने के साथ ही शिकायत की स्थिति तथा अन्य बिजली संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश बीएसएनएल के टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है, तो उपभोक्ता 0755-4314165 पर संपर्क कर कॉल सेंटर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

नशे में टल्ली मास्टरजी क्लास में आते ही सो गए

बच्चे पढ़ाई के लिए खड़े होकर करते रहे इंतजार, छिंदवाड़ा में स्कूल का ऐसा हाल

छिंदवाड़ा (नप्र)। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ कर्मचारियों की लापरवाही पूरे सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसा ही एक मामला जिले के खिरसाड़ोह संकुल अंतर्गत प्राथमिक शाला देवरी ढाना से सामने आया है, जहां पदस्थ शिक्षक गणेश इवनाती पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक लंबे समय से प्रतिदिन शराब के नशे में विद्यालय पहुंच रहे हैं। आरोप है कि वे बच्चों को पढ़ाने के बजाय समय से पहले घर भेज देते हैं और कई बार विद्यालय में ही नशे की हालत में पड़े रहते हैं।

क्लास की फर्श पर पड़े मिले शिक्षक- मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब शिक्षक विद्यालय परिसर में ही कक्षा के फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़े मिले। उस समय स्कूल में छोटे-छोटे बच्चे मौजूद थे, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं था। शिक्षक को इस हालत में देखकर ग्रामीण और अभिभावक मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते स्कूल परिसर में लोगों की भीड़ लग गई और घटना की जानकारी पूरे क्षेत्र में फैल गई। घटना के फोटो और वीडियो भी स्थानीय स्तर पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर- ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। शिक्षक के नशे में स्कूल आने की शिकायत लंबे समय से की जा रही है। उनका आरोप है कि शिक्षक नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लेते। कई दिनों तक बच्चों को बिना पढ़ाए ही वापस घर भेज दिया जाता है। इससे विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर लगातार गिर रहा है।

शिकायत के बाद भी नहीं कार्रवाई- ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार मौखिक और लिखित रूप से संबंधित अधिकारियों को शिक्षक के व्यवहार की जानकारी दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

डॉ: मुखर्जी काम्प्लेक्स में आरक्षित लिफ्ट के स्थान पर प्रस्तावित दुकानों की नीलामी निरस्त करें, ज्ञापन सौंपा

सोहागपुर। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट के लिए आरक्षित स्थान पर प्रस्तावित दो दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पर तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर को इसी संदर्भ में दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए। आयुक्त नगर प्रशासन एवं विकास संचनालय भोपाल के नाम को संबोधित करते ज्ञापन में कहा गया है कि सोहागपुर नगर में मुख्य बाजार स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स में हम सभी ने कुछ सालों पूर्व नगर पंचायत परिषद के द्वारा आयोजित सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से हम दुकानदारों दुकानें क्रय की थी। नीलामी के समय नगर पंचायत परिषद ने सार्वजनिक फ्लेक्स एवं बैनरों के माध्यम से इस कॉम्प्लेक्स को महानगरों तर्ज के अनुसार आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को विकसित किए जाने का प्रचार-प्रसार के सब्जबाग दिखाए थे। जिसमें में कॉम्प्लेक्स का आकर्षक एलीवेशन, लिफ्ट, एस्केलेटर तथा ऊपरी तल पर आवासीय फ्लैट जैसी अनेक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने उल्लेख किया था। उक्त सभी सुविधाएँ स्वीकृत नक्शे एवं प्राक्कलन का भी अभिन्न हिस्सा थीं।इसी सुविधाओं एवं नगर पंचायत परिषद के आश्वासनों पर विश्वास करते हुए हम सभी दुकानदारों ने नीलामी में बढ़-चढ़कर भाग लिया था। जिसमें दुकानदारों ने दुकानों की वास्तविक कीमत से 2 से तीन गुना अधिक राशि देकर दुकानें खरीदीं। किन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि आज दिनांक तक कॉम्प्लेक्स का निर्माण अधूरा है। वहीं अनेक घोषित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जिससे सभी दुकानदारों को आर्थिक एवं व्यावसायिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।इसी बीच नगर पंचायत परिषद ने दुकानदारों की आंख में धुल झोंकने के लिए प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों में निविदा सूचना न देकर एक स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 30.06.2026 को प्रकाशित ई-निविदा आमंत्रण सूचना के माध्यम से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों के नीचे लिफ्ट हेतु पूर्व से आरक्षित रिक्त स्थान को दो दुकानों में परिवर्तित कर उनकी नीलामी प्रस्तावित की गई है।चूंकि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी काम्प्लेक्स नगर का हृदय स्थल है । ऐसे में बेशक कीमती जगह को नगर पंचायत परिषद की बगैर दुकानदारों से मशविरा न करके नगण्य मूल्य पर नीलाम किया जा रहा है । उक्त दुकानों की वित्तीय निविदाएँ खोले जाने की तिथि 13.07.2026 निर्धारित है। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि यदि लिफ्ट हेतु आरक्षित स्थान पर दुकानों का निर्माण कर दिया जाता है, तो भविष्य में कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट लगाए जाने की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इससे न केवल स्वीकृत नक्शे एवं प्राक्कलन का उल्लंघन होगा। बल्कि सभी दुकानदारों के साथ नगर पंचायत परिषद को धोका देना सिद्ध होता है।यह एक गंभीर त्रुटि होगी । डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी काम्प्लेक्स आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉम्प्लेक्स के विश्वास में अधिक कीमत देकर दुकानें खरीदी थीं। यह हमारे साथ अन्याय एवं नगर पंचायत परिषद का यह निर्णय हमारी वैध अपेक्षाओं, आर्थिक हितों एवं भावनाओं के प्रतिकूल है। इससे हम सभी दुकानदार अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे कॉम्प्लेक्स की उपयोगिता एवं हमारी दुकानें व्यवासाय एवं दुकानों मूल्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।अतः हम सभी दुकानदार विनम्रतापूर्वक निवेदन करता है। कि जनहित एवं न्यायहित में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट हेतु आरक्षित स्थान पर प्रस्तावित दो दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाकर निरस्त करें। तथा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण स्वीकृत मूल नक्शे एवं प्राक्कलन के अनुरूप पूर्ण कराकर लिफ्ट, एस्केलेटर एवं अन्य घोषित सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान करने करें। इस अवसरों पर त्रिलोक बिनोले, मनीष मालवीय, संदीप शर्मा,ए वान, कमलेश कुशवाहा, रामबाबू सराठे, मनोज कुमार,प्रतीक सराठे ,अशोक इसरानी, रियाज शाह सुनीलकमार ,अंशुल जैन , गुढ़ा पाली, आर,के चौरसिया पार्षद भास्कर मांझी, पूर्व पार्षद मोहन कहार,नीरज चौधरी आदि उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

खाद्य विभाग एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया पौधरोपण

50 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

सीहोर (निप्र)। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य विभाग एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सीहोर के पचामा स्थित तिलहन संघ के गोदाम परिसर में संयुक्त रूप से पौधरोपण किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के 50 पौधे रोपे गए तथा उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। पौधरोपण कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने आसपास हरियाली बढ़ाने तथा पौधों की नियमित देखभाल करने की अपील की। इस अवसर पर कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश चंदेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जिला पंचायत सीईओ ने स्कूलों का किया निरीक्षण

बच्चों की आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का किया आकलन

सीहोर (निप्र)। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव ने विद्यार्थियों की आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का आकलन करने के उद्देश्य से बिलकिसगंज के जनजातीय ग्रामों सालीखेड़ा, पाटनी एवं बिलकिसगंज स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीयता के साथ संवाद किया तथा खेल-खेल में भाषा एवं गणित की आधारभूत अवधारणाओं पर आधारित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनकी सीखने की क्षमता का आकलन किया। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक इन गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने शिक्षकों के साथ चर्चा करते हुए उन्हें निर्देशित किया कि कक्षाओं में अधिक से अधिक गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति अपनाई जाए, जिससे बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित हो। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई एफएलएन शिक्षण-सामग्री का प्रभावी एवं नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी भाषा एवं गणित की आधारभूत दक्षताओं को सहज एवं आनंददायक तरीके से अर्जित कर सके। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं मजबूत आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान बच्चों के समग्र शैक्षणिक विकास की नींव है। इस दिशा में शिक्षकों की सक्रिय भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा प्रत्येक विद्यार्थी की नियमित प्रगति का सतत मूल्यांकन एवं आवश्यक शैक्षणिक सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

नर्मदापुरम में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

आरोपी का वाहन जब्त, 87 बल्क लीटर शराब बरामद

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी डॉ. राजीव प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्राम बांद्राभान में हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक वाहन जप्त कर तलाशी लेने पर 09 पेटियों में भरी कुल 87 बल्क लीटर देसी मदिरा और बीयर बरामद की गई। जप्त की गई शराब और वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 3,36,200 रुपये आंकी गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप योजना से मिली नई उम्मीद

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले के गंजबासौदा निवासी एक परिवार के लिए वर्ष 2024 अत्यंत कठिन साबित हुआ। 9 अक्टूबर 2024 को परिवार के मुखिया का आकस्मिक निधन हो जाने से परिवार गहरे आर्थिक संकट में आ गया। तीन बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनकी माता पर आ गई। विपरीत परिस्थितियों में भी माता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिन-रात मेहनत कर दूसरों के घरों में भोजन बनाने का कार्य किया, ताकि बच्चों की पढ़ाई और परिवार का पालन-पोषण जारी रह सके। इसी दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत दो बच्चों को प्रति माह 4,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी। इस सहायता से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और बच्चों की शिक्षा बिना किसी बाधा के निरंतर जारी रह सकी। आज तीनों बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह योजना उनके लिए केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं , बल्कि आत्मनिर्भरता, शिक्षा और बेहतर भविष्य की नई आशा भी लेकर आई है।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने सनखेड़ी में नवीन 33/11 केव्ही उपकेन्द्र का किया लोकार्पण

● सनखेड़ी सहित 09 गांवों के ग्रामीणों और किसानों को मिलेगा लाभ

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम सनखेड़ी में 05 एमव्हीए क्षमता के नवीन 33/11 केव्ही उपकेन्द्र का मप्र शासन के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि दो करोड़ 90 लाख रू लागत से निर्मित इस उपकेन्द्र के शुरू होने से सनखेड़ी सहित आसपास के नौ गांव के ग्रामीणों तथा किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सकेगी।

कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि दान देने वाले श्री नारायण सिंह बघेल को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर पौधरोपण भी किया गया। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। गांवों में निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति हो, लॉ-वोल्टेज की समस्या ना हो! इसके लिए नवीन उपकेन्द्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति होने से जहां बच्चों को पढ़ाई में सुविधा होगी, वहीं किसानों को भी सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा लो-वोल्टेज की समस्या से भी निजात मिलेगी। कार्यक्रम में विधायक डॉ चौधरी ने कहा कि इस नए 33/11 केव्ही

उपकेन्द्र के बनने से विशनखेड़ी, बिजौली, सनखेड़ी, देवलखेड़ी, आलमखेड़ा, रामगढ़, झिरनिया, महुआखेड़ा एवं हिम्मतगढ़ में पर्याप्त बिजली मिलेगी। पहले इन गांवों को मेहगांव फीडर से विद्युत सप्लाई होती थी। अब इस नए फीडर से विद्युत सप्लाई होगी, जिससे लॉ-वोल्टेज और बार-बार फॉल्ट होने की समस्या दूर होगी। अब फुल वोल्टेज विद्युत मिलेगी, जिससे किसानों के पंप और घरेलू उपकरण सुरक्षित रहेंगे। इन गांवों के साथ ही मेहगांव के फीडर से जिन गांवों को विद्युत सप्लाई होगी, वहां भी गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और आगे नहीं छोड़ेंगे। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया है, नवीन स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल भवन आदि का निर्माण कराया गया है। विधायक डॉ चौधरी ने क्षेत्र में स्वीकृत किए गए नवीन विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा ने भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर मप्र विद्युत वितरण कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की बडी कार्यवाही

इटारसी में 530 वर्गफुट शा0 जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर नर्मदापुरम श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में एसडीएम इटारसी श्री नीलेश शर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने इटारसी शहर स्थित भूमि शीट नंबर-42, खसरा नंबर-1.396 हे. शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर करीब 10 लाख रुपये कीमत की 530 वर्गफुट जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासनिक टीम पहले मौके पर पहुंची और अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी। इसके बाद जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पूरी कार्रवाई तहसीलदार श्रीमती सुनीता साहनी के नेतृत्व में संपन्न हुई। मौके पर पर्याप्त प्रशासनिक अमला और नगर पालिका का दल तैनात रहा। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से की गई। एसडीएम श्री नीलेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण न करें। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम पंचायत दमदम मे स्वच्छता अभियान के तहत की गई नाले नालियों की साफ सफाई

ग्राम वासियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई

नर्मदापुरम (निप्र)। आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत दमदम में व्यापक स्वच्छता अभियान संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य संरक्षण तथा वर्षा ऋतु के दौरान जलजनित एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से गांव के सभी वार्डों में साफ-सफाई का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। यह अभियान सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक (जीआरएस) के संयुक्त मार्गदर्शन एवं सतत निगरानी में संचालित हो रहा है। अभियान के अंतर्गत गांव की छोटी-बड़ी नालियों की गहन सफाई कर जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाया जा रहा है, ताकि वर्षा के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही सार्वजनिक स्थलों, गलियों एवं अन्य स्थानों पर जमा कचरे का नियमित रूप से संग्रहण एवं सुरक्षित निष्पादन किया जा रहा है, जिससे स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित हो सके। ग्राम पंचायत द्वारा मानसून के दौरान डेंगू, मलेरिया, हैजा सहित अन्य मौसमी एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम को प्राथमिकता देते हुए समय रहते आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। पंचायत प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से भी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने, जलभराव नहीं होने देने तथा स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की गई है।

ताप्ती जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित

ताप्ती उद्गम स्थल के समग्र विकास के लिए तैयार होगी व्यवस्थित मास्टर प्लानिंग

बैतूल (निप्र)। ताप्ती जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर जनपद पंचायत मुलताई में बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुलताई विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीतू परमार, श्रीमती वर्षा गढ़ेकर, जनपद अध्यक्ष श्रीमती नानी बाई डहारे, कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, एसडीएम श्री राजीव कहार सहित ताप्ती मंदिर ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पवित्र ताप्ती नगरी मुलताई को बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अभी से व्यवस्थित और दूरदर्शी प्लानिंग तैयार की जाए। बैठक में ताप्ती उद्गम स्थल के समग्र विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार तथा पर्यटन की दृष्टि से आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुलताई विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख ने कहा कि ताप्ती उद्गम स्थल के विकास की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही परिसर

में उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कुंड के आसपास बेहतर लाइटिंग व्यवस्था, कवर्ड नालियों का निर्माण तथा श्रद्धालुओं के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य वेलकम गेट को आकर्षक डिजाइन के साथ विकसित कर आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार ने घाट विकास, पेयजल व्यवस्था, स्मार्ट शौचालय, कंट्रोल रूम सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए विस्तृत प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभी से समग्र विकास योजना तैयार की जाए। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा के लिए भक्त निवास निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने ने एसडीएम एवं नगर पालिका सीएमओ को ताप्ती मंदिर के आसपास स्थित जर्जर भवनों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही छोटे तालाब को स्टेप-सेटिंग सीढ़ीनुमा घाट के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

जिले में दस्तक अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर विश्वकर्मा ने अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

दस्तक अभियान का प्रथम चरण 14 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिला टॉस्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिला टॉस्क फोर्स की बैठक कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में 14 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले दस्तक अभियान के प्रथम चरण के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सीएमएचओ, सभी एसडीएम तथा महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि अभियान की सफलता के लिए जरूरी है कि सभी विभाग समन्वय के

साथ कार्य करें। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 09 माह से 5 साल तक के बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे डायरिया, निमोनिया, एनीमिया और कुपोषण की पहचान कर उनका त्वरित उपचार सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत स्वास्थ्य अमले द्वारा घर-घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। साथ ही 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग नियंत्रण के लिए बच्चों को दो ओआरएस पैकेट एवं 14 जिंक टेबलेट दी जाएगी। 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को आयु-अनुरूप विटामिन ए का अनुपूरण किया जाएगा। इसी प्रकार 5 वर्ष से कम आयु के सेम तथा मेम की श्रेणी सुधार के साथ ही अन्य बाल्यकालीन बीमारियों से ग्रसित बच्चों की पहचान, प्रोटोकॉल अनुसार उपचार व रैफरल कर प्रबंधन किया जाएगा। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री तथा अन्य अधिकारियों से कहा कि अभियान का प्रथम चरण 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिले में कोई भी लक्षित बच्चा छूटे नहीं इसके लिए कार्ययोजना बनाकर अभी से तैयारियां शुरू की जाए। उन्होंने सभी एसडीएम तथा संबंधित जिला अधिकारियों से कहा कि अभियान के दौरान प्रत्येक चरण की सतत् मॉनीटरिंग की जाए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनमोल पोर्टल पर सभी गर्भवती महिलाओं की डाटा एन्ट्री करना जरूरी है, यह हाईरिस्क महिलाओं के स्वास्थ्य की मॉनीटरिंग में मददगार है। पोर्टल पर नियमित रूप से एन्ट्री हो तथा एन्ट्री के दौरान सही जानकारी दर्ज की जाए, यह सुनिश्चित कराएं। उन्होंने जिले में जलजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही पीएचई विभाग को निर्देश दिए कि पेयजल स्त्रोतों की नियमित जांच की जाए, नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिले यह सुनिश्चित कराएं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय सहित स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा तथा संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

खेतों में पर्याप्त नमी के बाद ही करें बोवाई

रायसेन (निप्र)। मौसम की अनिश्चितता के बारे में लगाए जा रहे अनुमानों के बाद भी किसान भाईयों को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। खरीफ की बुआई के लिए कुछ सावधानियां अपनाकर किसान उत्पादन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। कुछ जिलों में अल्प वर्षा को देखते हुए खरीफ फसलों की बोवाई में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक खेतों में पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक बुआई करना जोखिम पूर्ण हो सकता है। कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने वैज्ञानिकों के परामर्श से किसानों को सलाह दी है।

संचालक कृषि श्री उमाशंकर भार्गव ने इस संबंध में मैदानी अमले को किसानों से सतत संपर्क करने के अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। सामान्य रूप से 4 इंच यानि लगभग 1 बालिश्त की गहराई तक नमी होने तथा बतर आने के बाद बोवाई की आदर्श स्थिति मानी जाती है। वर्तमान में पूरी तरह मानसून की सक्रियता न होने के कारण बोवाई के लिए किसानों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्तता हो उन्हें मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिये ढैंचा या सनई की बुवाई हरित खाद के रूप में करना चाहिये। जिन क्षेत्रों में पूर्व में वर्षा हुई है, वे भी हरित खाद या ग्रीन मैन्योरिंग हेतु फसलें बो सकते हैं।

बुवाई के लिए तैयार खेतों में आधार खाद जैसे गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट एवं उर्वरक जैसे सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और जिंक सल्फेट तथा जिप्सम आदि को खेत में बोवाई या छिड़काव द्वारा मिलाया जा सकता है। कृषि सलाह के अनुसार किसान भाई, सोयाबीन के बीज का अंकुरण परीक्षण कर 70 प्रतिशत से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का उपयोग करें। रोग एवं कीट प्रतिरोधी उपयुक्त ऐसी किस्मों का चयन करें जिनकी जल मांग भी कम हो। इसके लिये कृषि अधिकारियों से परामर्श लेना उपयोगी होगा। बुवाई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशकों एवं जैव उर्वरकों से उपचारित करना आवश्यक है। सोयाबीन फसल की बुवाई में जलभराव एवं सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु रिज-एंड फरो सीड ड्रिल, ब्रॉड बेड एंड फरो सीड ड्रिल अथवा हस्तचालित सीड डिब्लर का प्रयोग करना उपयोगी है।

● कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार प्रारंभ हुई खरीदी प्रक्रिया

शमशाबाद में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का शुभारंभ

विदिशा (निप्र)। जिले के किसानों को उनकी मूंग उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने और समर्थन मूल्य योजना का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में मंगलवार को नटेरन विकासखंड के विपणन सहकारी समिति मर्या. शमशाबाद स्थित मूंग उपार्जन (खरीदी) केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार प्रारंभ हुई खरीदी प्रक्रिया के पहले ही दिन ग्राम डफरयाई कलां के किसान श्री नारायण सिंह धाकड़ एवं श्री नीरज धाकड़ की मूंग उपज का समर्थन मूल्य पर सफलतापूर्वक उपार्जन किया गया। उपार्जन केन्द्र का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार श्री दर्शनलाल नेगी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जगदीश गुर्जर, उपार्जन केंद्र नोडल श्री अभिषेक जैन, केंद्र प्रभारी श्री देवेंद्र सिंह राजपूत, एमपीडब्लूएलसी के श्री आकाश साहू, सर्वेयर श्री शुभम कोरी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सबसे पहले केन्द्र में मौजूद किसानों का स्वागत करते हुए समर्थन मूल्य खरीदी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। खरीदी केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक तौल प्रणाली के माध्यम से पूरी पारदर्शिता एवं व्यवस्थित तरीके से उपज का तौल एवं उपार्जन किया गया। इससे किसानों को निष्पक्ष एवं सुगम व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक किसान की उपज का नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से उपार्जन हो। उप संचालक कृषि श्री सचिन जैन ने किसानों से अपील की कि वे शासन द्वारा निर्धारित स्लॉट के अनुसार ही अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पहुंचें तथा सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। उन्होंने कहा कि निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने से खरीदी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से संचालित होगी तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीदी केंद्र पर पेयजल, छायादार विश्राम स्थल, बैठने की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशासन ने खरीदी केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए किसान हितैषी वातावरण तैयार किया है,जिससे किसानों को सहज और सुरक्षित तरीके से अपनी उपज बेचने का अवसर मिल सके।

अधिकारियों ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का कार्य 10 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि में सभी पंजीकृत एवं पात्र किसानों की उपज का नियमानुसार उपार्जन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने किसानों से निर्धारित तिथि एवं स्लॉट के अनुसार खरीदी केंद्र पहुंचकर समर्थन मूल्य योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही यह भी आश्वस्त किया गया है कि पूरी खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित एवं किसान हितैषी तरीके से संचालित की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो सके।

बुजुर्ग ने फांसी लगाकर सुसाइड किया

पैरालिसिस के बाद डिप्रेशन में थे, छत के शेड के सहारे बनाया था फंदा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बैरागढ़ थाना क्षेत्र में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान मनोहर लाल रैकवार पिता मोहनलाल रैकवार निवासी बेटा गांव बैरागढ़ के रूप में हुई है। वे पेशे से प्लंबर थे। करीब आठ महीने पहले उन्हें पैरालिसिस (लकवा) का अटैक आया था, जिसके बाद से उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी और वे घर पर ही रह रहे थे।

पुलिस के अनुसार बीमारी के कारण उनके शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। इससे उन्हें रोजमर्रा के सामान्य काम करने में भी काफी परेशानी होती थी। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते वे मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगे थे और अवसाद (डिप्रेशन) की स्थिति में थे।

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी

शुक्रवार सुबह उनकी पत्नी नींद से उठकर घर की पहली मंजिल पर पहुंची तो देखा कि मनोहर लाल पाइप के सहारे फंदे पर लटके हुए हैं। उन्होंने शोर मचाया। सूचना मिलने पर पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और उनकी मदद से शव को फंदे से नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।

सूचना मिलते ही बैरागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में बीमारी और उससे उपजी मानसिक परेशानी के चलते यह कदम उठाने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तंत्र-मंत्र, ट्रेडिंग के नाम पर महिला से 85 लाख ठगे

जिन्न का डर दिखाया; पति की मौत के बाद भी लेता रहा पैसा

दुर्ग-भिलाई (नप्र)। छत्तीसगढ़ के भिलाई में घरेलू परेशानियां दूर करने, तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ कराने का झांसा देकर महिला से करीब 85 लाख रुपए की ठगी की गई है। आरोपी ने महिला को कभी जिन्न और प्रेत बाधा का डर दिखाया, कभी निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का वादा किया। गुप्त पूजा और पति के एक्सीडेंट होने की बात कर डराया। इसके बावजूद पति की सड़क हादसे में मौत हो गई, जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी और अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगता रहा। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को आरोपी के मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। पुलिस उसके बैंक खातों और पैसों के लेनदेन की जांच की जा रही है। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है।

रायपुर में हुई थी पहचान- दरअसल, संगीता कश्यप ने 16 दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 2023 में रायपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात जबलपुर के रहने वाले पवन बधोरिया से हुई थी।

ये दोनों कहीं दिखें तो तुरंत दें भोपाल पुलिस को सूचना

मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम, डबल मर्डर केस के हैं संदिग्ध

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की राजधानी में बुजुर्ग पति-पत्नी की हत्या हुई थी। घटना के एक सप्ताह से अधिक हो गए हैं लेकिन पुलिस अभी आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। अब इस केस से जुड़े दो संदिग्ध आरोपियों की पुलिस ने तस्वीर जारी की है। साथ ही 50000 रुपए का इनाम घोषित किया है।

ऐशबाग के अंबेडकर कॉलोनी में हुई थी हत्या

दरअसल, ऐशबाग की अंबेडकर कॉलोनी में बुजुर्ग जोड़े की हत्या की जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। गुरुवार को दो संदिग्धों की बेहतर क्वालिटी के सीसीटीवी तस्वीरें मिली हैं। भोपाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई जानकारी इनके बारे में हो तो शेयर करें, जिससे की संदिग्धों की पहचान हो सके।

50000 रुपए का इनाम

इसके साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आरोपियों की जानकारी देने वाले लोगों के लिए 50000 रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। घटनास्थल से कोई फिंगरफ्रिंट या पैरों के निशान नहीं मिले हैं। घर की अन्य कीमती चीजें और सामान भी सुरक्षित पाए गए हैं।

नंबर किए जारी

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि जो कोई भी उन संदिग्धों को जानता या पहचानता है, वह तुरंत ऐशबाग के एसएचओ से 9329540284 पर, क्राइम ब्रांच के एसीपी से 9425959497 पर या पुलिस कंट्रोल रूम से 0755-2555922 पर संपर्क करे।गौरतलब है कि बुजुर्ग जोड़े का कोई संतान नहीं है। अंबेडकरनगर स्थि घर की कीमत एक करोड़ से अधिक है। उसे बेचने की बात चल रही थी। हालांकि वह पड़ोसियों से कहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में रहता है। पुलिस इस हत्या को संपत्ति विवाद ही मानकर जांच चल रही है। मगर कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है।

दो प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग तेज

कर्मचारी बोले-गैस-पेट्रोल सहित हर सामान महंगा फिर भी 7 महीने से नहीं बढ़ा भत्ता, सरकार ने बचाए 425 करोड़

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस) के अधिकारियों को जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स भी इसी तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार से जल्द घोषणा करने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार राहत दे नहीं रही।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे चुकी है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में कार्यरत करीब 850 अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भी केंद्रीय दर से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी समान लाभ मिलना चाहिए।

12 लाख से अधिक कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा लाभ

कर्मचारी संघ का कहना है कि प्रदेश के करीब 7.50 लाख कार्यरत कर्मचारियों और 4.50 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलना चाहिए। वर्तमान में कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। संगठन ने इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की मांग की है।

बढ़ती महंगाई का दिया हवाला

उमाशंकर तिवारी ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उद्देश्य बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देना होता है। उन्होंने बताया कि मार्च से जून के बीच घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 89 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मई महीने में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कई बार वृद्धि हुई, जबकि खाद्य पदार्थ भी लगातार महंगे हुए हैं। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है।

1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग

कर्मचारी संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की तरह प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के आदेश जल्द जारी किए जाएं, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

भाभी की पत्थर से हत्या कर युवक ने फांसी लगाई

रायसेन में महिला का शव खेत में और पेड़ पर लटका मिला देवर का शव

रायसेन (नप्र)। रायसेन जिले के गैरतगंज थाना क्षेत्र में एक देवर द्वारा अपनी भाभी की कथित तौर पर पत्थर से हमला कर हत्या करने और इसके बाद स्वयं फंदे पर लटककर जान देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

खेत ले जाने के बाद किया हमला- गैरतगंज थाना प्रभारी डीपी लोहिया के अनुसार, गुरुवार को आरोपी अपनी भाभी को बाइक से खेत लेकर गया था। रात में लौटते समय उसने रास्ते में बाइक रोककर महिला के सिर पर पत्थर से हमला किया। गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया।

तलाश के दौरान मिला महिला का शव- देर रात तक दोनों के घर नहीं लौटने और फोन बंद मिलने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान खेत के पास महिला का शव मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

अगली सुबह पेड़ पर लटका मिला आरोपी- महिला की हत्या के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। शुक्रवार सुबह मृतका के पिता खेत पहुंचे तो उन्होंने आरोपी का शव एक पेड़ पर फंदे से लटका देखा। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।

चार साल पहले भी इसी पेड़ पर हुई थी आत्महत्या

पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस पेड़ पर आरोपी का शव मिला, उसी पेड़ पर करीब चार वर्ष पहले उसके छोटे भाई ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस इस तथ्य को भी जांच में शामिल कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या और आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजनों के बयान, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।